हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंकः मई–जून 2016

दिल्ली

ਦਿੱਲੀ

دلّی

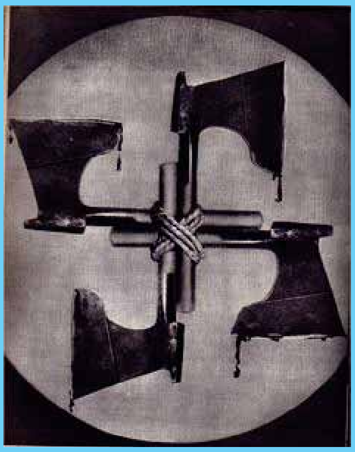

फ़ासिस्ट

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि वह मनुष्य है

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि वह जनप्रतिनिधि है

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि उसके पास आधार कार्ड है

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि वह शाकाहारी है

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि मुद्दा विकास है

(मैंने बिनास सुना)

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि
उसके पास तीस फ़ीसदी का बहुमत है
सत्तर फ़ीसदी के अल्पमत की तुलना में

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि
गाँधी को हमने नहीं मारा,
हममें से किसी ने उन पर गोली चला दी

मैंने कहा कि आप फ़ासिस्ट हैं
तो उसने कहा कि अब जो कुछ हैं हमीं हैं !

–देवी प्रसाद मिश्र

जलसा ब्लॉग (http://jalsapatrika.blogspot.in/) से साभार।

दिल्ली

अंक : मई–जून 2016

प्रधान सम्पादक
सज्जन सिंह यादव

विशेष निदेशक
संदीप मिश्र

सम्पादक
डॉ. पंकज श्रीवास्तव

सम्पादकीय सहयोग
नलिन चौहान
कंचन आजाद, विनोद गुप्ता
चन्दन कुमार, अमित कुमार
मनीष कुमार, उर्मिला बेनिवाल

छाया चित्र
सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

"दिल्ली" पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता
प्रधान सम्पादक
दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय
दिल्ली सरकार
खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
दूरभाष : 23819046, 23817926
फैक्स : 23814081
ई–मेल : delhidip@gmail.com

दिल्ली में साहित्य महोत्सव

दिल्ली में समर कैंप

इस अंक में...

हिन्दी

दिल्ली का बजट 2
दिल्ली वालों को सेहत का तिहरा डोज 5
शिक्षा का कायाकल्प 6
फीस घटाने को मजबूर हुए स्कूल 9
एलिवेटेड कॉरीडोर से जुड़ेगी दिल्ली 11
मोहल्ला रक्षक दल 13
दिल्ली में ऑड–ईवन फिर से 14
दिल्ली नहीं रहा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 18
तीसरा यमुना एक्शन प्लान शुरू 19
केजरीवाल दुनिया के 50 नेताओं में 20
दिल्ली हॉट में बनेगा डॉ. कलाम का संग्रहालय 21
धूमधाम से मनाई डॉ. अंबेडकर की जयंती 24
संक्षेप में 28

पंजाबी

ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ! 1
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਿਹਰਾ ਡੋਜ਼ ! 4
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 5
'ਐਲੀਵੇਟੇਡ ਕਾਰੀਡੋਰ' ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਦਿੱਲੀ. 8
ਮੁਹੱਲਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 10
ਦਿੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦਿਲ ਸੇ, ਆਡ-ਈਵਨ ਫਿਰ ਸੇ ! 11

उर्दू

دہلی سرکار کا جادوئی بجٹ 1
دہلی والوں کو صحت کا تیہرا ڈوز 4
دہلی میں ایجوکیشن کا کایا کلپ دہلی سرکار کے سرکاری اسکول پڑے 5
ایلیویٹیڈ کاریڈور سے جڑے گی دہلی 8
محلّہ محافظ فورس کریگی خواتین کی حفاظت 10
دہلی بولے دل سے آڈ-ایون پھر سے 11

सुविधाएँ हज़ार, पर नहीं टैक्स की मार !

क्या आपने कभी सुना कि कोई सरकार अपने बजट का लगभग चौथाई हिस्सा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने पर ख़र्च कर दे? या ख़ज़ाने का 16 फीसदी हिस्सा लोगों की सेहत दुरुस्त रखने में लगा दे? साथ ही न कोई नया टैक्स न पुराने टैक्स में बढ़ोतरी। यह अनोखी बात है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने बजट के ज़रिये एक बार फिर साबित किया कि दिल्ली के आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 28 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2016–17 के लिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार का बजट पेश किया तो निगाह में सिर्फ़ आम आदमी था। उन्होंने इस बार 46,600 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जबकि पिछली बार 41,129 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ था। बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा–'हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा के लिए साल 2016–17 में 10,690 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण की नहीं, प्रबंधन की जरूरत है।'

यह बजट ऐसा था कि किसी को उँगली उठाने का मौक़ा नहीं मिला। 30 मार्च को यह बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। शुरू में सरकार ने कम कीमत वाले फुटवियर व वस्त्रों पर पाँच फीसदी कर का प्रावधान किया था लेकिन इसे वापस ले लिया गया। इससे व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने विधानसभा परिसर पहुँचकर सरकार को धन्यवाद देते हुए जश्न मनाया।

विधानसभा में बजट पर भाषण देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की देश और दुनिया भर में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा–"लोग कह रहे हैं कि अब दूसरी सरकारें भी बजट बनाना दिल्ली की सरकार से सीखें। हम सत्ता में आए तो कहा जा रहा था कि इन लोगों को गवर्नेंस नहीं आता। अब वह भी हमने करके दिखा दिया है। वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार हमारी तारीफ में लिख रहे हैं। फार्च्यून मैग्जीन ने हमारा नाम दुनिया के 50 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है।"

कम कीमत वाले फुटवियर और कपड़ों पर पाँच फीसदी कर के प्रस्ताव को वापस लेने को यू–टर्न कह जाने का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके किसी फैसले से जनता को कोई परेशानी हो रही है तो आधी रात को भी यू–टर्न ले लेंगे। किसी का रोजगार नहीं छिनने देंगे। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि वह भी एक्साइज ड्यूटी के मामले पर यू–टर्न ले और अपने अहंकार को छोड़ ज्वेलर्स के कारोबार को बचा लें।

वहीं वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे जनता को परेशानी हो। सरकार ने दूसरे साल के बजट में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सहित जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धनराशि प्रस्तावित की है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निगमों के लिए बजटीय आवंटन 1,000 करोड़ रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के नगर निगमों के लिए पिछले वर्ष बजटीय आवंटन 5,908 करोड़ रुपये था। बाद में इसे बढ़ाकर 5,999 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस साल बजट में इसे बढ़ाकर 6,919 करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बीजेपी नियंत्रित नगर निकायों को धन का सही तरीके से उपयोग करने की भी सलाह दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि एमसीडी इस राशि का उपयोग कर्मचारियों को सही समय पर वेतन देने में करेगी।

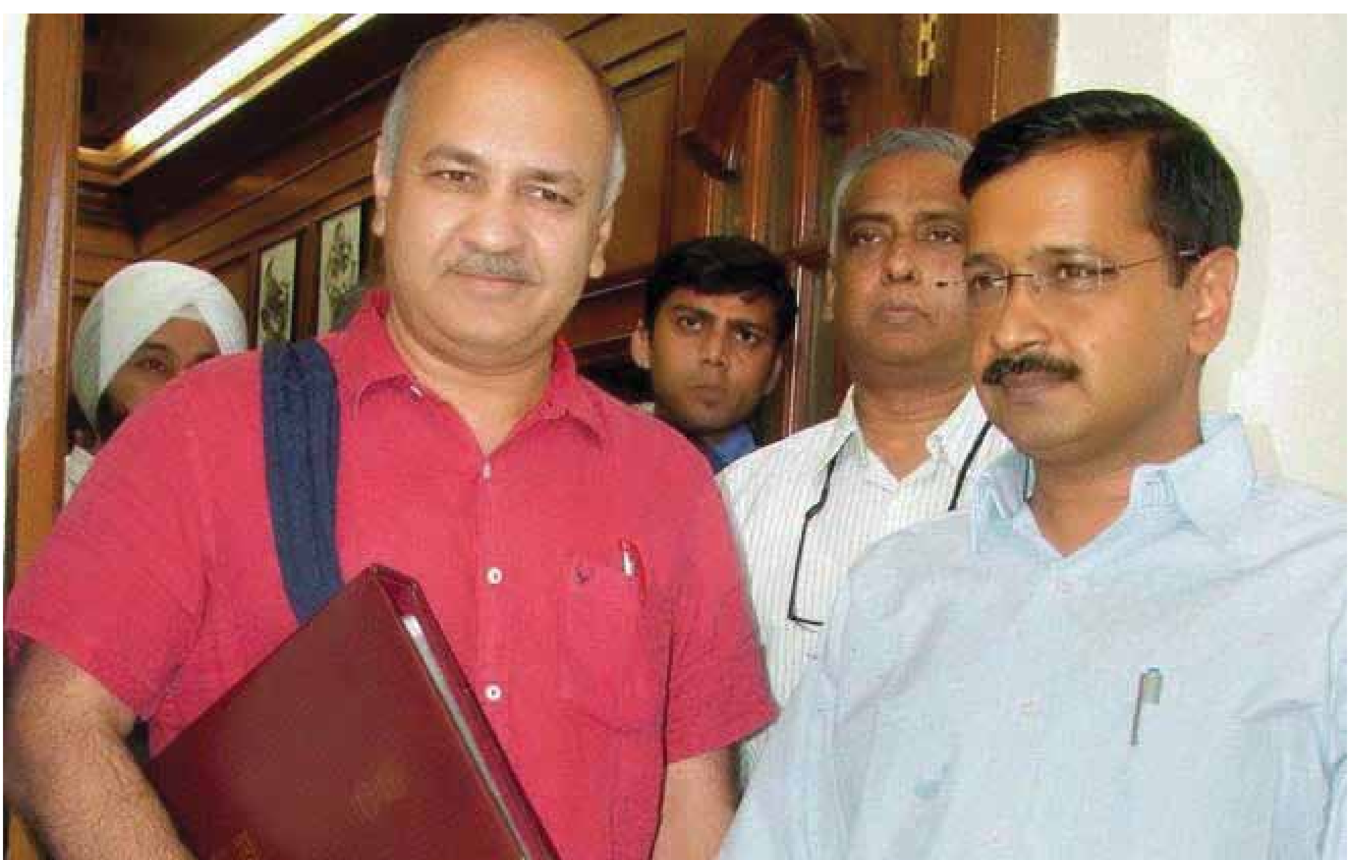

दिल्ली सरकार के बजट की 10 ख़ास बातें

1 दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी और इसके लिए बजट में 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2 दिल्ली के नगर निगमों का बजट 1000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है यानि निगमों को अब सालाना 5908 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6919 करोड़ रुपये मिलेंगे।

3 पर्यावरण अनुकूल वाहनों, बैटरी संचालित और हाइब्रिड वाहनों पर वैट को 12.5% से घटा कर 5% कर दिया गया है।

4 इसके अलावा मिठाइयों, नमकीन, सभी रेडीमेड गारमेंट, मार्बल और सभी फुटवियर तथा स्कूल बैग पर भी वैट 12.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

5 स्वराज निधि योजना में 350 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और अब हर विधानसभा में मोहल्ला सभा बनेगी और उसका बजट बनेगा। पूरी दिल्ली में करीब 3000 मोहल्ला सभाएँ होंगी।

6 बजट का एक चौथाई हिस्सा शिक्षा के लिए और 16 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। कुल 10,690 करोड़ रुपये शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रखे गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए साल के अंत तक 1000 मोहल्ला क्लीनिक के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। 100 मोहल्ला क्लीनिक तुरंत खोले जाएंगे। 150 पॉली क्लिनिक खोलने की योजना है जिनमें से 22 चालू हो चुके हैं।

7 आम आदमी कैंटीन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में कई जगह शुरू होने वाली इस कैंटीन में महज 5 से 10 रुपये में खाना मिलेगा।

8 सभी स्कूलों के हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तमंत्री सिसोदिया के मुताबिक सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा।

9 दिल्ली सरकार के बजट में शहर में वाई–फाई और मुख्य सड़कों के साथ साइकिल लेन बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

10 दिल्ली के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। ई–रिक्शा के लिए सब्सिडी 15000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। 248 नयी मेट्रो फीडर बसें आएंगी, मेट्रो के लिए 763 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ■

दिल्ली वालों को सेहत का तिहरा डोज़ !

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओ में बेहतरी के लिए पिछली बार से डेढ़ गुना ज्यादा बजट दिया है। यह कुल बजट का 16 फीसदी है। यह साबित करता है कि वह आम लोगों की सेहत को लेकर कितनी फिक्रमंद है। 2016–17 के लिए कुल स्वास्थ्य बजट 5,259 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 3200 करोड़ प्लान बजट है।

सरकार की सबसे महात्वाकांक्षी और असरदार योजना है कि लोगों को अस्पतालों में हर हाल में मुफ्त दवा मिले। इसके लिए सरकार ने 410 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट भाषण के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि सरकार का मकसद केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना नहीं, बल्कि हेल्थ मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए तीन स्तरों वाला सिस्टम बनाने की योजना पर काम कर रही है जो देश के किसी भी सूबे में नहीं हुआ।

दरअसल, दिल्ली सरकार का इरादा है कि आम जनता निजी नर्सिंग होमों या अस्पतालों के दुश्चक्र में बेवजह न फँसने पाये। अगर लोगों को बीमारी की शुरुआत में, घर के पास ही जाँच और इलाज की सुविधा मिल जाये तो पैसा और वक्त तो बचेगा ही, बीमारी बढ़ने भी नहीं पायेगी। मोहल्ला क्लीनक का विचार इसी चिंता की उपज है जहाँ डॉक्टर, दवा और तमाम जाँच की सुविधा होगी। पूरी दिल्ली में ऐसे 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने हैं जिनमें सौ बहुत जल्द शुरू हो जाएँगे। इस परियोजना की तारीफ़ अमेरिका समेत दुनिया भर के अख़बारों में हो रही है।

सेहत सुरक्षा का दूसरा चक्र पॉलीक्लीनिक के रूप में होगा जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर और सभी प्रकार की जाँच की सुविधा होगी। अब तक 22 पॉलीक्लीनिक शुरू हो चुके हैं और ऐसे कुल 150 पॉलीक्लीनिक का जाल पूरी दिल्ली में बिछेगा।

तीसरा चक्र होगा बड़े अस्पतालों का जहाँ बहुत मजबूरी में ही किसी मरीज़ को जाना होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त दवा पाना मरीज़ का नागरिक अधिकार है। अगर किसी अस्पताल में कोई ख़ास दवा मौजूद नहीं है तो प्रभारी उसे खुद मँगाकर मरीज़ को देने के लिए बाध्य होगा।

उसके बाद कौन मरीज नहीं कहेगा–मुस्कराइये कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है !

दिल्ली में शिक्षा का कायाकल्प !

देश में सरकारी शिक्षा–व्यवस्था की बदहाली का रोना रोने वालों के लिए दिल्ली की ख़बरें सुखद आश्चर्य की तरह हैं। कहाँ तो सरकारी स्कूल का मतलब बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ माना जाता है और कहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से होड़ लेने में जुटे हैं। कुल बजट का लगभग 24 फीसदी सिर्फ शिक्षा पर खर्च करने का ऐलान करके केजरीवाल सरकार ने बता दिया कि उसके इरादे क्या हैं। दुनिया भर में इस अनोखी पहल की चर्चा है। अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं।

बुनियादी ढाँचा, शिक्षक और पाठ्यक्रम–दिल्ली सरकार इन तीन मसलों पर अपना पूरा ध्यान दे रही है। यानी स्कूल में कमरे, फर्नीचर से लेकर अन्य बुनियादी सुविधायें बेहतर हों, शिक्षकों में पढाने का उत्साह हो

और पाठ्यक्रम नये जमाने के हिसाब से हो। बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने का सपना तभी पूरा हो सकेगा।

दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने की अगुवाई कर रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि शिक्षक–छात्र अनुपात ठीक करने से लेकर स्कूलों में पढ़ाई–लिखाई के माहौल की राह में आने वाले हर रोड़े को सरकार हटायेगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में 8000 नये क्लासरूम बनाने का इरादा जताया जो 200 नये स्कूलों के बराबर हैं। इन कमरों का निर्माण चल रहा है और अगली जुलाई से ये काम में आ सकेंगे। शिक्षामंत्री सिसोदिया ने बताया कि 21 नये स्कूलों की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है जिनमें डबल शिफ्ट में 42 स्कूल चलाये जा सकते हैं।

एस्टेट मैनेजर–बजट में हर स्कूल में एक एस्टेट मैनेजर नियुक्त करने का प्रावधान है। उसकी जिम्मेदारी स्कूल की इमारत और परिसर के रखरखाव की होगी। एस्टेट मैनेजर स्कूल के हालत की वीडियो क्लिप रोजाना अपने डिप्टी डायरेक्टर को भेजेंगे। प्रधानाचार्यों पर बोझ घटेगा और पूरी तरह पठन–पाठन की निगरानी पर ध्यान दे पायेंगे।

शिक्षकों की गुणवत्ता–बजट में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दिलाने का प्रावधान किया गया है। उन्हें हार्वर्ड, कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे मशहूर विश्वविद्यालयों में भेजा जायेगा ताकि वे बाक़ी दुनिया में शिक्षा जगत के परिवर्तनों को जान–परख सकें। इसके लिए बजट में 102 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जबकि पिछली बार केवल 9.4 करोड़ का बजट था। सरकार के मुताबिक 5500 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अतिथि शिक्षको को नियमित करने की प्रक्रिया भी चल रही है और 9623 नए पद भी सृजित किये जा रहे हैं। शिक्षकों को अब जनगणना जैसे कामों में नहीं लगाया जाएगा ताकि पढ़ाई बाधित न हो।

खेल पर ध्यान–खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। खेल संगठनों के लिए स्कूलों के खेल मैदान खोलने और 55 स्कूलों में विश्वस्तरीय फुटबॉल ग्राउंड और टेनिस कोर्ट तैयार करने की योजना है। बजट में स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी खोलने का भी प्रावधान है।

वोकेशनल ट्रेनिंग–दिल्ली के 205 स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अब सभी स्कूलों में ऐसा करने के लिए 105 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। इसके अलावा 2006 में बंद की गई स्टेट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम सरकार फिर शुरू करेगी। कम से कम 50 हजार नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है।

उच्च शिक्षा–सरकार उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भी कई कदम उठा रही है। इसके तहत अंबेडकर युनिवर्सिटी के रोहिणी और धीरपुर में नये कैंपस शुरू होंगे। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ को नई इमारत में शिफ्ट किया जायेगा। आचार्य नरेंद्रदेव, भगिनी निवेदिता और गुरु गोविंद सिंह आई.पी युनिवर्सिटी के कैंपस का निर्माण भी 2016–17 में शुरू हो जाएगा। ■

दिल्ली के सरकारी स्कूल पड़े निजी स्कूलों पर भारी !

इस बार सीबीएसई 12वी के परीक्षा परिणामों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों को रिजल्ट के मामले में मात दे दी। नतीजों के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों का पास प्रतिशत 88.98 रहा जबकि निजी स्कूलों मे सिर्फ 86.67 फीसदी। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों मे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तमाम प्रयोग कर रही है जिसका असर साफ नजर आया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की मेहनत ने माहौल बदला और विद्यार्थियों में भी पढ़ने की ललक पैदा हुई। दिल्ली के 130 स्कूलों का परिणाम 100 फीसदी रहा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों से बेहतर परिणाम पेश किया है, इसके लिए दिल्ली की शिक्षा टीम को बधाई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुझे टीम पर गर्व है। उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी सरकारी स्कूलों की इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने स्कूलों मे टॉप करने वाले 4 छात्रों सहित आल इंडिया टॉप करने वाली छात्रा सुकृति गुप्ता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के निजी स्कूलों पर लोगों की निर्भरता कम करने व सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की अपेक्षा बेहतर बनाने की दिशा मे काम कर रही है, उसे इन परीक्षा परिणामो से ओर अधिक बल मिलेगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के सिस्टम को बदलने के लिए पिछले सवा साल से बड़े कदम उठाये है, उन्ही नतीजों की ओर ये परिणाम इशारा करते हैं।

फ़ीस कम करने को मजबूर हुए प्राइवेट स्कूल !

सरकार की सख्ती के चलते दिल्ली में पहली बार निजी स्कूल ने न सिर्फ फीस घटाई बल्कि वसूली गयी बढ़ी फीस वापस करने को मजबूर भी हुए। सरकार ने इस सबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए कहा था कि सरकारी ज़मीन पर बने निजी स्कूल बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते। ऐसे स्कूलों को टेकओवर कर लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार के सख्त रवैये को देखते हुए अभिभावकों का हौसला बढ़ा और उन्होंने दस्तावेज़ों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराई। सरकार ने कार्रवाई करते हुए कथूरिया पब्लिक स्कूल का टेकओवर किया और मैक्सफोर्ट स्कूल को इस संबंध में नोटिस दिया। मैक्सफोर्ट के रोहिणी और पीतमपुरा ब्रांच को टेकओवर करने की तैयारी है। जाँच में दोनो जगह ईडब्लूएस कोटे में धाँधली के अलावा वित्तीय गड़बड़ियाँ भी पाई गईं।

स्कूल जरूरी रिकार्ड भी नहीं दे पाया जिसे 'डेल्ही स्कूल एजूकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973' के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।

सरकार की सख्ती को देखते हुए अलकनंदा के कालका पब्लिक स्कूल, मयूर विहार फेस–3 के सलवान पब्लिक स्कूल, ओल्ड राजेंद्र नगर के जी.डी. सलवान जैसे कई

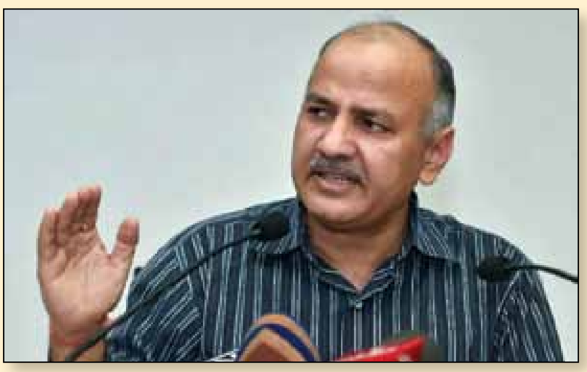

फ़ीस लेकर मर्सिडीज़ नहीं ख़रीदने दूँगा-सिसोदिया

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार की इजाज़त से निजी स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं लेकिन उन्हें इसे केवल संस्थान के विकास पर खर्च करना चाहिए न कि मर्सिडीज़ खरीदने पर या फिर 'शिक्षा की अपनी दुकान के साम्राज्य' को बढ़ाने पर।

उन्होंने कहा कि कई स्कूल प्रबंधक फीस बढ़ाकर मर्सिडीज कार खरीदते हैं या फिर आलीशान घर बनाते हैं। अलग–अलग राज्यों और शहरों में अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। जिसे यह सब करना हो वह आय के दूसरे स्रोतों से करे, फीस के पैसे से नहीं।

नामी–गिरमी स्कूलों ने फीस घटा दी। यही नहीं डीपीएस जैसे नामी गिरामी स्कूल की कई ब्रांचों ने भी फीस घटा दी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। यही नहीं, कुछ स्कूलों ने बिना अनुमति वसूली गई बढ़ी फीस वापस भी कर दी। अभिभावकों ने डीपीएस की मथुरा रोड, रोहिणी और वसंतकुंज शाखाओं के बारे में मनमानी फीस बढ़ाने की शिकायत की थी। इस पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर शिक्षा निदेशक सौम्या गुप्ता ने पत्र लिखकर सख़्त चेतावनी जारी की और स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अति गरीब श्रेणी (ईडब्लूएस) एडमीशन को लेकर गलत जानकारी देने वाले स्कूलों के खिलाफ एफआईआर होगी। नियम के मुताबिक निजी स्कूलों को 25 फीसदी एडमीशन ईडब्लूएस श्रेणी में करने होते हैं, लेकिन ऐसा न करके स्कूल गलत जानकारी दे देते हैं। सरकार की सख्ती से स्कूलों की मनमानी रुक पाई और ईडब्लूएस कोटे के तहत सही लोगों को एडमीशन मिला। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कोटे के तहत एडमीशन पाने वाले बच्चों को कॉपी–किताब और युनिफार्म देना भी स्कूल की जिम्मेदारी है।

सरकार ने नई पहल करते हुए कैग से जुड़े एकाउंटेंट से निजी स्कूलों के खातों की जाँच कैग से कराने की तैयारी कर ली है। जिन संस्थानों ने स्कूल चलाने के लिए सरकारी जमीन ली है, उनकी बाकायदा जाँच की जाएगी। नियम है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस को मुनाफे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकार ने कुल मिलाकर करीब 400 स्कूलों को फीस बढ़ोतरी वापस लेने के लिए मजबूर किया है। ■

'एलिवेटेड कॉरीडोर' से जुड़ेगी दिल्ली

बढ़ती आबादी और वाहनों के बोझ ने दिल्ली की सड़कों पर बुरा असर डाला है। आये दिन जाम की और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार के ऑड–ईवन प्रयोग को जनता ने सराहा तो है, लेकिन कई और मोर्चों पर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड कॉरीडोर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सड़क परिवहन को दुरुस्त करने के लिए 2208 करोड़ रुपये का योजना बजट बनाया है जो कुल बजट का 11 फीसदी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि पायलट योजना के तहत दो एलिवेटेड कॉरीडोर बनाने की अहम योजना पर काम शुरू हो गया है। अगर हवाई सड़कों के जरिये दिल्ली की दूरियों को नापने की योजना कामयाब रही तो सड़कों पर जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी।

सरकार के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए (अरविंदो मार्ग) तक बारापुला नाले पर एलिवेटेड रोड का दूसरा चरण इसी साल पूरा हो जाएगा। बारापुला नाले पर 1261 करोड़ रुपये लागत वाले सराय काले खाँ से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दोनों परियोजनाओं पर 400 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

इसी के साथ सरकार ने एलिवेटेड रोड के सफर को मेट्रो की तर्ज पर आरामदायक बनाने की योजना बनाई है। सरकार दो एलिवेटेड बीआरटी कॉरीडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। एक कारीडोर आनंद विहार टर्मिनल से पीरगढ़ी तक (ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर) होगा। यह 29 किलोमीटर का होगा। दूसरा एलिवेटेड बीआरटी कॉरीडोर 29 किलोमीटर का (नार्थ–साउथ कॉरीडोर) होगा। यह वजीराबाद से एयरपोर्ट तक बनाया जायेगा। साथ ही अन्य चार मार्गों पर एलिवेटेड कॉरीडोर, एनएच 24 बाईपास से लोदी रोड तक एक भूमिगत सुरंग और खजूरी खास से भोपुरा बॉर्डर तक कॉरीडोर की फिजीबिलिटी स्टडी करायी जा रही है। ईस्ट–वेस्ट और नार्थ–साउथ मॉडल को पूरी दिल्ली में लागू किया जायेगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली की 11 सड़कों को री–डिजाइन किया जायेगा ताकि पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए भी पर्याप्त जगह हो। नए डिजाइन की सड़कों में ग्लास लिफ्ट, स्ट्रीट लाइट और वर्षा जल संचयन के उपाय किये जायेंगे। आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद की 20 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर साइकिल ट्रैक और फुटपाथ भी बनाने का प्रस्ताव है।

मोहल्ला रक्षक दल करेगा महिलाओं की सुरक्षा

आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी इसकी झलक दिखी जब सरकार ने मोहल्ला रक्षक दल के गठन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। सरकार के मुताबिक 2016–17 में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला रक्षक दल गठित करने की योजना है। इसके अलावा सरकार ने 42000 डार्क स्पॉट्स (अंधेरे कोनों) की पहचान की है जिन्हें जल्दी ही प्रकाश व्यवस्था से जोड़ दिया जायेगा। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए सरकार ने बजट में 1068 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में सिविल डिफेंस वालंटियर्स को लेकर मोहल्ला रक्षक दल बनाया था जिस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसे देखते हुए अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला रक्षक दल गठित किये जायेंगे। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली पुलिस, कुछ एनजीओ और अन्य एजेंसियों की मदद से सरकार ने 421 सड़कों पर 42000 डार्क स्पॉट्स को चिन्हित किया है। इन जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को खतरा रहता है। 114 करोड़ रुपये खर्च करके इन स्थानों पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। 2016–17 तक यह काम पूरा कर लिया जायेगा। ■

सीसीटीवी के लिए 200 करोड़

सरकार ने सीसीटीवी लगाने के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा है। सरकार के मुताबिक डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी व कैमरे लगाये जा चुके हैं। कुछ बसों में मुफ्त वाई–फाई सुविधा भी शुरू की जा चुकी है और बसों में 4000 मार्शल भी तैनात किये गये हैं। सरकार के मुताबिक सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी लगाने की योजना है।

दिल्ली बोली दिल से, ऑड-ईवन फिर से !

क़ामयाब रहा 15-30 अप्रैल का दूसरा चरण

दिल्ली की जनता ने ऑड–ईवन स्कीम को एक बार फिर कामयाब बनाकर साबित कर दिया कि अगर राजनीतिक नेतृत्व के इरादों में ईमानदारी हो तो जनता सहयोग देने में कभी पीछे नहीं रहती। जनवरी के सफल प्रयोग के बाद अप्रैल महीने की 15 से 30 अप्रैल के बीच इस प्रयोग को दोहराया गया और नतीजों ने साबित किया कि प्रदूषण हटाने, जाम से निजात दिलाने और लोगों में सहयोग की भावना विकसित करने का मकसद काफ़ी हद तक पूरा हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस स्कीम की सफलता के लिए दिल्ली की जनता को बधाई दी है।

इस बार ऑड–ईवन स्कीम की सफलता को लेकर संदेह के दो मुद्दे थे। एक तो, पिछली बार की तरह इस बार स्कूल बंद नहीं थे, दूसरे यह भी कहा जा रहा था कि भीषण गर्मी की वजह से लोग निजी वाहन से चलने का मोह नहीं छोड़ पायेंगे। लेकिन जनता ने सारी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए इस योजना को सफल बनाया। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि

अब दिल्ली के पास ऑड–ईवन का विंटर (सर्दी) और समर (गर्मी), दोनो मॉडल हैं। दोनों माडलों का अध्ययन करके आगे की योजना बनाई जाएगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि इस योजना को असफल बनाने के लिए राजनीतिक अड़चन भी खड़ी की गई। ऑटो हड़ताल कराने की पूरी कोशिश की गई लेकिन सरकार ने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर जाम की शिकायत आई लेकिन ऐसा स्थानीय स्तर पर चल रहे निर्माणकार्यों की वजह से हुआ न कि डीटीसी बसों के ब्रेक डाउन से।

उन्होंने बताया कि डीटीसी बसों के ब्रेकडाउन में 50% की कमी आई। इस भयंकर गर्मी में पहले 400 से 500 बसों का ब्रेकडाउन होता था, जो ऑड–ईवन के दौरान घटकर 200 तक रह गया है। साथ ही इनमें से ज्यादातर बसों को 20 से 35 मिनट के अंदर अटेंड कर लिया जाता था। इसके चलते जाम की स्थिति नहीं हो रही है। इन बसों में चलने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। उन्होंने उदाहरण दिया कि ऑड–ईवन से पहले 11 अप्रैल को डीटीसी बसों ने 35362 फेरे लगाये लेकिन 18 अप्रैल को यह तादाद 42,003 हो गई। डीटीसी बसों 18 अप्रैल को 41,11,327 लोगों ने सफर किया जबकि 11 अप्रैल को 38,56,426 लोगों ने सफर किया था।

पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ विशेष लोगों को छूट दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के अलावा शेष अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के वाहनों को इस नियम से छूट मिली। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री इस छूट के दायरे में नहीं थे। बैटरी और अधिकृत एजेंसियों द्वारा लगाई गई सीएनजी किट से चलने वाली कारों पर यह नियम लागू नहीं था। साथ ही दो पहिया वाहन चालकों को भी शामिल नहीं किया गया। एंबुलेंस, दमकल विभाग, पुलिसिया वाहन, यातायात विभाग के वाहनों को भी छूट थी। अकेली महिला के स्कूल छोड़ने–लाने के लिए अभिभावकों को छूट दी गई बशर्ते बच्चा स्कूली युनीफार्म में हो।

ऑड–ईवन के दौरान लाखों गाड़ियों के सड़क पर न उतरने से प्रदूषण में कमी स्वाभाविक थी। इसके अलावा जाम के बिना दिल्ली की सड़कों पर चलना सफर को सुहाना बना रहा था जो एक असंभव सपने की तरह था।

ऑड-ईवन के दौरान प्रदूषण घटा

ऑड–ईवन पार्ट–2 के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी आई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) की मानिटरिंग से पता चला है कि 2015 की तुलना में 2016 की 17 से 26 अप्रैल के बीच पीएम 2.5 का स्तर कम रहा। वहीं ज्यादातर दिन पीएम 2.5 का स्तर सामान्य के आसपास ही रहा।

"कौन कहता है सम–विषम कामयाब नहीं है? आज लगभग अस्सी किलोमीटर गाड़ी चलाई। शाम चार से नौ के बीच। रश आवर। नेहा 24, इंडिया गेट, अकबर रोड, तीनमूर्ति, रिंग रोड, पंजाबी बाग़, पश्चिम विहार, आज़ादपुर रोड, तीसहजारी, आईएसबीटी, गीता कालोनी रोड और फिर नेहा 24। यानी व्यस्ततम रास्ते।

जैसे कोई दूसरा शहर हो। या इतवार हो। कोई जाम नहीं। दमघोंटू प्रदूषण नहीं।

हे विजय गोयलों, पप्पू यादवों, तुम अपनी नवाबी के लिए दिल्लीवालों का साफ़ हवा में जीने का हक़ छीन लेना चाहते हो तो जनता देशभक्ति के नाम पर तुम्हारा ज़िंदाबाद करेगी? दर चिरकुट समझ रखा है?"

(26 अप्रैल को दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक आशुतोष कुमार की फेसबुक पर टिप्पणी)

सफर का दावा है कि ऑड–ईवन स्कीम के लागू होने के बाद एक दिन भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में नहीं पहुँचा।

दिल्ली से सबक़ लेंगे मास्को और बीजिंग

दिल्ली की ऑड–ईवन स्कीम की सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जाम और प्रदूषण से जूझ रहे दुनिया के तमाम मशहूर शहर दिल्ली की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और यहां की कामयाबी को अपने यहाँ दोहराना चाहते हैं।

रूस की राजधानी मास्को से आये एक डेलीगेशन ने 26 अप्रैल को इस सिलसिले में दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से उनके दफ्तर में मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली में इस योजना को लागू करने और कामयाब बनाने की दिशा में उठाये गये कदमों की जानकारी दी। मीटिंग में डीटीसी, डीएमआरसी, पुलिस के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। डेलिगेशन में मास्को के मेयर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर और डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डिवेलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्टी हेड भी थे।

प्रतिनिधिमंडल इस बात से काफी प्रभावित हुआ कि दिल्ली का सारा सार्वजनिक परिवहन सीएनजी पर आधारित है। सदस्यों ने दिल्ली सरकार की परिवहन व्यवस्था से जुड़ी तमाम योजनाओं में दिलचस्पी दिखाई ताकि मास्को को भी नई राह मिल सके।

उधर, चीन पहले ही दिल्ली सरकार की ऑड–ईवन योजना की तारीफ कर चुका है। चीन की राजधानी बीजिंग के म्यूनिसपल कमीशन में परिवहन उपायुक्त झूतियान के मुताबिक नंबर नियम दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में मददगार साबित हो रहा है। इसका स्थायी प्रभाव देखा जा सकता है अगर इसे लंबे समय तक माकूल तरीके से लागू किया जाए। गौरतलब है कि नंबर योजना सबसे पहले चीन के बीजिंग में शुरू की गई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिलीं थी अब दोबारा वहाँ इस योजना

को शुरू किया जा सकता है। झूइन कहा की दिल्ली की इच्छाशक्ति देकर वे प्रभावित हुए है। दिल्ली में जहां 25 लाख कारें है वहीं बीजिंग में 55 लाख कारें है।

सर्ज प्राइसिंग के नाम पर नहीं मिली लूट की छूट !

ऑड–ईवन स्कीम के लागू रहने के दौरान ओला और उबेर जैसी टैक्सी सेवाओं ने सर्ज प्राइसिंग (माँग बढ़ने के साथ दाम बढ़ाने) के नाम पर किराये में भारी बढ़ोतरी कर दी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे दिन–दहाड़े लूट बताते हुए कहा कि सरकार ब्लैकमेलिंग बरदाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कुछ टैक्सीवालों ने कहा है कि अगर उन्हें मनमाना किराया वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया तो वे टैक्सी आपूर्ति नहीं करेंगे। ऐसे टैक्सीवालों को दिल्ली सरकार कड़ा सबक सिखायेगी। उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये जाएंगे।

सरकार की सख्ती को देखते हुए सामान्य से तीन गुना किराया वसूलने की जुगत भिड़ा रही कंपनियों के हाथ–पाँव ढीले पड़ गये। उन्हें समझ में आ गया कि सरकार उनकी दाल गलने नहीं देगी। ऑड–ईवन स्कीम के दौरान दिल्ली की जनता को आम दिनों के हिसाब से ही टैक्सी किराये का भुगतान करना पड़ा।

इसी के साथ सरकार ने ऐप आधारित टैक्सियों के लिए नई नीति बनाना तय किया है। इसके मुताबिक टैक्सी वालों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराया वसूलने की ही अनुमति होगी। राजधानी में चलने वाली सभी ऐप आधारित टैक्सियों के लिए यह नीति लागू होगी, भले ही वे रेडियो इकोनॉमी टैक्सी हों या काली–पीली टैक्सी, किराया तय हिसाब से ही लेना होगा।

ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वालों को लगा था कि सर्ज प्राइसिंग पर सरकार केवल ऑड–ईवन के दौरान ही रोक लगायेगी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें लूट की छूट कभी भी नहीं दी जाएगी।

दिल्ली अब नहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर!

आखिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कोशिशों और ऑड–ईवन जैसे प्रयोगों ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताज़ा रिपोर्ट ने दिल्ली पर लगे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के तमगे को हटा दिया है। यही नहीं, दिल्ली टॉप टेन प्रदूषित शहरों की सूची में भी नहीं है। दिल्ली को इस सूची में 11वें नंबर पर रखा गया है।

रिपोर्ट में 103 देशों के 3000 शहरों के प्रदूषण का स्तर मापा गया है। यह स्थान पीएम (बारीक कण) 2.5 के आधार पर है। पीएम 10 के आधार पर दिल्ली 25वें स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से जारी शहरी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में ईरान के ज़बोल शहर को सबसे प्रदूषित माना गया है। भारत के इलाहाबाद और ग्वालियर शहर दुनिया में प्रदूषण के मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।

रिपोर्ट में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 भारत के ही हैं। 2014 के डाटाबेस में शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल थे। इस बार पीएम 2.5 के आधार पर ग्वालियर और इलाहाबाद जैसे छोटे शहर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पटना को छठाँ स्थान मिला है वहीं रायपुर 7वें स्थान पर है। दिल्ली ने अपने प्रदूषण स्तर में सुधार किया है वहीं अहमदाबाद का स्तर भी स्थिर रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक पटना, ग्वालियर और इलाहाबाद की स्थिति चिंताजनक है। ये आंकड़ें पीएम 2.5 स्तर के हैं। उल्लेखनीय है कि पीएम 10 की अपेक्षा पीएम 2.5 स्वास्थ्य पर ज्यादा बुरा असर डालता है।

गौरतलब है कि 2014 की रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। 14 फरवरी 2015 को सत्ता संभालने वाली केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड–ईवन स्कीम चलाई जिसका असर अब दिखने लगा है। यह स्कीम दिल्ली में दो चरणों में चलाई गई। पहली बार 1 जनवरी से 15 जनवरी तक और फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इस स्कीम के अंतर्गत ऑड तारीख को ऑड नंबर की कार और ईवन तारीख को ईवन नंबर की कार से सफर करने की अनुमति होती है। इस योजना से प्रदूषण की समस्या के साथ–साथ दिल्ली को जाम से निजात मिली थी।

2014 में दिल्ली में बारीक कणों का स्तर काफी ज्यादा पाया गया था। पिछली बार इस रिपोर्ट को तैयार करने में डब्लूएचओ ने 1600 शहरों के प्रदूषण को नमूनों को अपनी लिस्ट में शामिल किया था। जबकि इस बार पिछली बार के मुकाबले 1400 और शहरों को शामिल किया गया है। ■

केंद्र और दिल्ली सरकार की 'टीम इंडिया' साफ़ करेगी यमुना

ढाई साल बाद यमुना में एक बूँद भी गंदा पानी नहीं गिरेगा-कपिल मिश्र

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेदों की चाहे जितनी चर्चा हो, लेकिन जब मसला दिल्ली के हित का हो तो सरकार किसी मतभेद को आड़े नहीं आने देती। ऐसा ही मसला है यमुना की सफाई का। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस मसले पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम किया जाएगा।

7 मई को आईटीओ छठ घाट पर तीसरे यमुना एक्शन प्लान के तहत 825 करोड़ की योजना की शुरूआत करते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने माना कि स्थिति गंभीर है और यमुना सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीम इंडिया के रूप में काम करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए एसटीपी का निर्माण होगा, नए नदी तटबंध बनाए जाएंगे। 2.5 करोड़ रुपये की लागत से छठ घाट की मरम्मत होगी। साथ ही, यमुना की लगातार सफाई करते रहने के लिए 4.5 करोड़ रुपये की लागत वाला ट्रैश स्कीमर लगाया गया है।

दिल्ली सरकार के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि यमुना की सफाई के लिए दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में जब भ्रष्टाचार होती है तो नदी भी गंदी हो जाती है। जब व्यवस्था बदलती है तो नदी भी स्वच्छ होगी। इसका असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल में यमुना को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। उस संकल्प के साथ केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे।

जल मंत्री ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में कई एजेंसियां हैं, जो यमुना से जुड़े मामलों को देखती हैं। इसके चलते योजनाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए दिल्ली में एक एजेंसी की जिम्मेदारी तय करने की नीति पर काम चल रहा है। जल्द ही उसे हकीकत का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के लिए एक विस्तृत योजना जल बोर्ड तैयार कर रहा है। 45 दिन में योजना तैयार कर उसका प्रारूप केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगले ढाई साल के बाद यमुना में दूषित जल का एक बूंद भी ना गिरने पाए।

नयी योजना के तहत दोनों सरकारें साथ मिलाकर जलमल शोधन के लिए वजीराबाद और ओखला के बीच एसटीपी का निर्माण करेंगी, नदी की तलहटी को साफ करेंगी और ठोस कचरे को ट्रैश स्कीमर के जरिए हटाएंगी, नदी तटबंध बनाएंगी और छठ घाट की मरम्मत करेंगी। ■

अरविंद केजरीवाल दुनिया के 50 महानतम नेताओं में !

मशहूर फार्च्यून पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम नेताओं की अपनी सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया है। केजरीवाल इस सूची में स्थान पाने वाले भारत के अकेले नेता हैं। पहला स्थान अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को मिला है।

फार्च्यून की ''वर्ल्डस 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स'' की तीसरी सालाना सूची में दुनिया भर से कारोबार, सरकार, और कला के क्षेत्र की उन चुनिंदा हस्तियों को शामिल किया गया है जो दुनिया बदल रहे हैं और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल (47 साल) को 42वाँ स्थान दिया गया है।

फार्च्यून ने केजरीवाल को नई दिल्ली की सड़कों पर ऑड–ईवन योजना के तहत वाहन संख्या सीमित कर प्रदूषण रोकने के उनके प्रयासों के लिए इस सूची में जगह दी है।

पत्रिका ने केजरीवाल की सराहना करते हुए लिखा है जब केजरीवाल ने धुंध से निपटने के लिए ऑड–ईवन योजना का खाका पेश किया तो कई लोगों ने संदेह जताया। नयी दिल्ली को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कहा था।

फार्च्यून ने कहा इस जनवरी में परियोजना के उल्लेखनीय नतीजे मिले। सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम हुई, पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण सांद्रण में 13 फीसदी की कमी आई और नागरिकों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिली। पत्रिका ने कहा कि नेतृत्व का मतलब प्रजानायक होना या लोकप्रियता नहीं होता बल्कि दुनिया भर के लोगों द्वारा उस तरीके की तारीफ करना होता है जिसके जरिये आप जीवन बेहतर बनता है।

अमेरिकी पत्रिका ने केजरीवाल और इटली के रायसी शहर के मेयर डोमेनिको लुकानो का संदर्भ देते हुए कहा सरकारी अधिकारी ने प्रदूषण से निपटने के लिए अपने करियर को दाँव पर लगा दिया वहीं इतालवी मेयर ने अपने नन्हें शहर में पश्चिम एशिया के प्रवासियों का स्वागत किया। लुकानो को सूची में 40वां स्थान मिला है।

पत्रिका में कहा गया है यहां आप जिन नेताओं से मिलेंगे उन्हें आप जानते हैं और कुछ नए हैं। ये नेता दुनिया के भविष्य के लिए आपके आंकलन को बेहतर बनाएंगे। कुछ आपको उनकी राह पकड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जिन्हें आप नहीं जानते हैं वह प्रेरक नेता के तौर पर शायद आपको आपकी अपनी क्षमता के बारे में फिर सोचने के लिए प्रेरित करें। ■

दिल्ली कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव

दिल्ली हाट में बनेगा डॉ. कलाम का संग्रहालय

पूर्व राष्ट्रपति और महान विज्ञानी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक बनाने के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। डॉ. कलाम स्मारक दिल्ली हाट में बनेगा जहाँ उनके सार्वजनिक और निजी जीवन से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा।

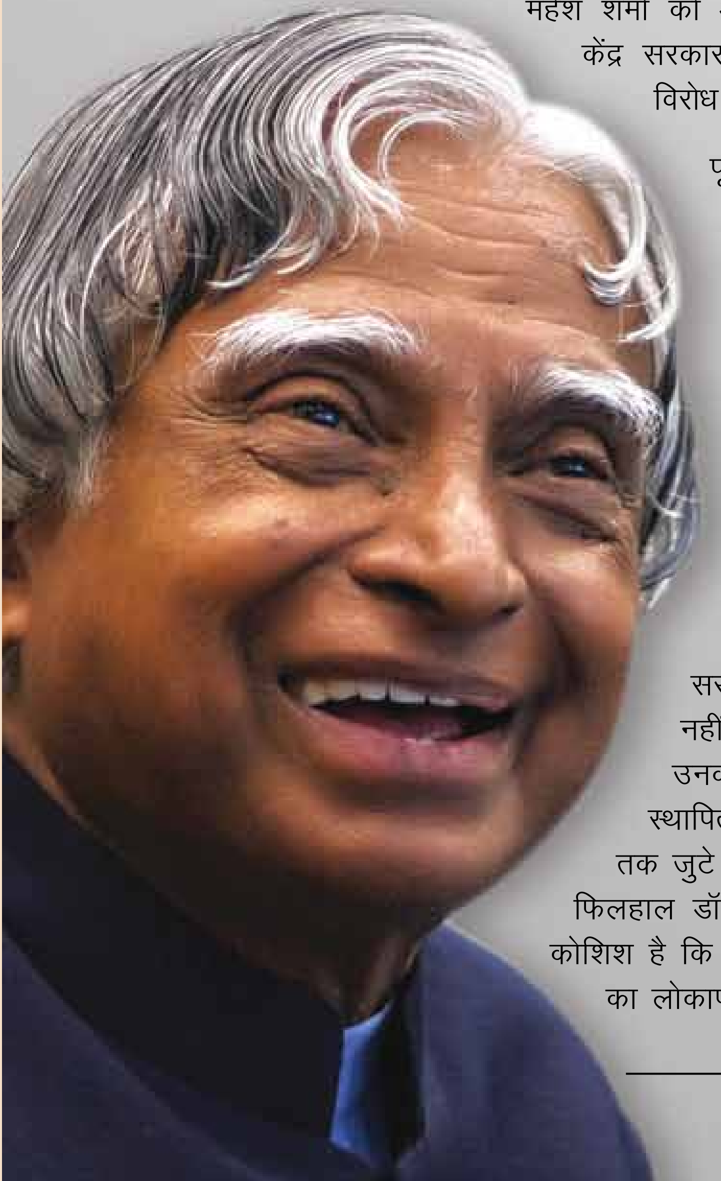

ग़ौरतलब है कि डॉ. कलाम के निधन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने उनका सामान उनके पैतृक स्थान रामेश्वरम भेज दिया था। यही नहीं, परिजनों की माँग थी कि उनके सरकारी आवास 10, राजाजी मार्ग को ही उनका स्मारक बना दिया जाये लेकिन माँग को ठुकराते हुए यह बँगला केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा को आवंटित कर दिया गया। केंद्र सरकार के इस कदम का भारी विरोध हुआ था।

पूर्व राष्ट्रपति के बड़े भाई एपीजे मोहम्मद मुथु मीरान लेब्बल मरैकयार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर नई दिल्ली में कलाम नेशनल सेंटर फॉर नॉलेज डिस्कवरी स्थापित करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे उचित मानते हुए ऐलान किया कि दिल्ली सरकार डॉ. कलाम का स्मारक बनवायेगी। पर्यटन और जल मंत्री कपिल मिश्र अप्रैल के पहले हफ्ते में डॉ. कलाम का सामान लाने खुद रामेश्वरम गये। दिल्ली सरकार ने तया किया है कि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम को स्मारक निर्माण का काम सौंपा जाएगा।

सरकार के मुताबिक डॉ. कलाम के स्मारक निर्माण में पैसा आड़े नहीं आयेगा। स्मारक में डॉ. कलाम से जुड़ी निजी चीजों के अलावा उनके ऑडियो–वीडियो भी होंगे। साथ ही डॉ. कलाम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बच्चों के बीच वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में अंत तक जुटे रहने वाले डॉ. कलाम के स्मारक से नई पीढ़ी प्रेरणा ले सकेगी। फिलहाल डॉ. कलाम का सामान एक अस्थायी संग्रहालय में रखा गया है। कोशिश है कि डॉ. कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई को दिल्ली हाट में स्मारक का लोकार्पण हो जाये। ■

दिल्ली में समर कैंप

शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान देने वाली दिल्ली सरकार के इरादों का असर दिखने लगा है। भीषण गर्मी के बावजूद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस बार अलग ही रौनक नजर आई। एक नई पहल करते हुए सरकार ने पहली बार ग्रीष्मकालीन शिविर या समर कैंप आयोजित करने का फैसला किया।

कक्षा छह के विद्यार्थियो के लिए आयोजित इस कैंप के प्रति भारी उत्साह दिखा। 11 से 31 मई के बीच आयोजित हुए कैंप के पहले दो दिनों में ही 551 सरकारी स्कूलों के करीब 44000 छात्रों ने भागीदारी की।

कक्षा पांच तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके जब छात्र छठी कक्षा में जाते हैं तो एक नया दौर शुरू होता है। कैंप का मकसद था कि कक्षा छह में आने वाले छात्रों का नए अंदाज़ में स्वागत किया जाये ताकि वे अपने नये सफ़र को लेकर सहज बन सकें। कैंप ने इस मकसद को बखूबी पूरा किया। इस दौरान छात्रों को अपने अंदर छिपी तमाम प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिला। किसी ने कलम उठाई तो किसी ने कूची। किसी ने अपने हुनर से रंगीन कागज़ को कलाकृतियों में तब्दील कर दिया। गायन, वादन से लेकर अभिनय क्षमता के निखार का अवसर मिला। यही नहीं, शनिवार को अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने बच्चों के साथ तरह–तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया।

समर कैंप में शामिल बच्चों को खेल–खेल में तमाम गंभीर विषयों की जानकारी दी गई। जल संकट, खाद्य संकट, प्रदूषण, कूड़ा निस्तारण, पर्यावरण जैसे मसलों पर बच्चों ने कलात्मक प्रतिक्रिया जताई। छात्रों के समूह बनाकर उनके बीच पढ़ने, लिखने और गणित से जुड़े सवालों की प्रतियोगिताएँ हुई।

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार और इस पूरे आयोजन की कमान संभाल रहीं आतिशी मारलेना ने कहा कि सरकार का इरादा निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों की बीच का अंतर मिटाना है। दिल्ली के सरकारी स्कूल एक नये रंग और ऊर्जा के साथ नये सत्र में छात्रों का स्वागत कर रहे हैं।

खेल–खेल में शिक्षा पाने का यह तरीका छात्रों को काफी भाया। सजे–धजे स्कूल और क्लासरूम सरकारी स्कूलों की पुरानी छवि से उलट नजारा पेश कर रहे थे। छात्रों के बीच 'हमारी दिल्ली' विषय पर एक पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई। तय हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ पोस्टर को दिल्ली पर्यटन विभाग की ओर से छापा जायेगा। इस पूरे आयोजन में "प्रथम" और "साझा" नाम के दो स्वयंसेवी संगठनों ने ख़ास सहयोग दिया। 1500 अतिथि शिक्षकों को कैंप के लिए खासतौर पर ट्रेनिंग दी गई। ■

धूमधाम से मनाई डॉ. अंबेडकर की जयंती

वे सावरकर पढायें, हम अंबेडकर पढ़ायेंगे-केजरीवाल

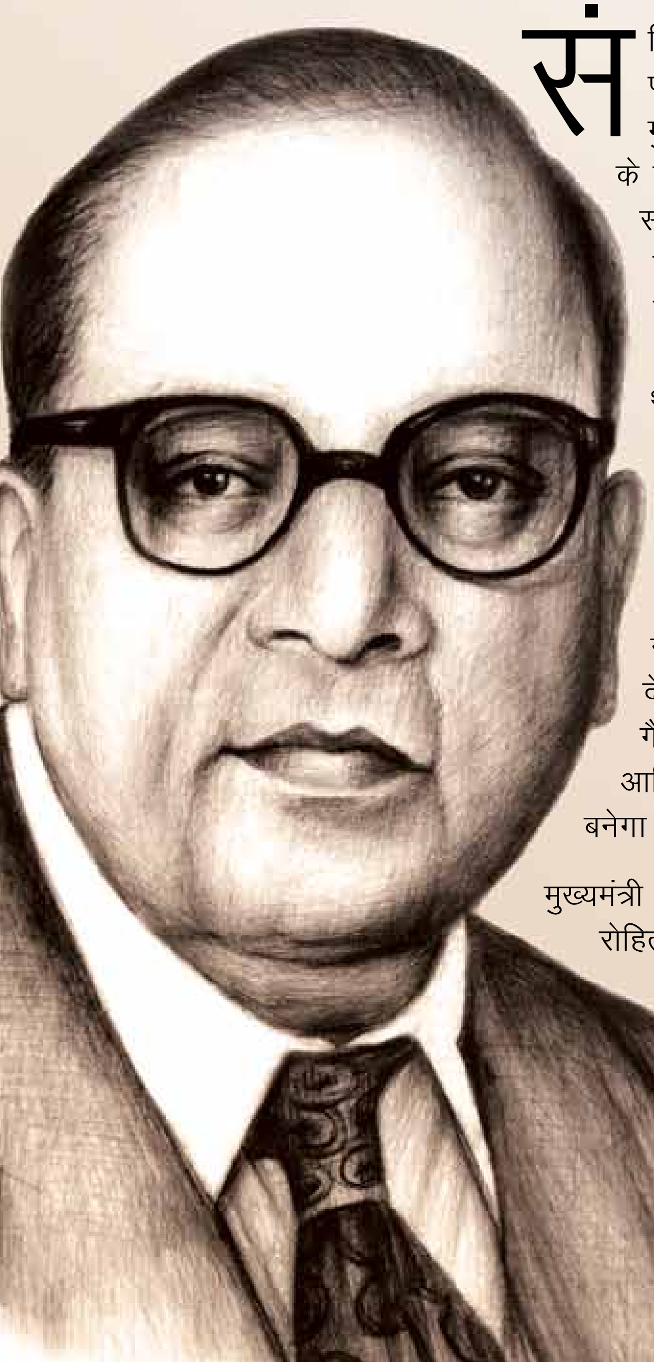

संविधान निर्माता, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125 वीं जयंती पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी सरकार डा. अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान में डा. अंबेडकर का सपना बसता है इसलिए इसका हर शब्द उनके लिए पवित्र संकल्प की तरह है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकारी की नीतियों को विभाजनकारी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर (जिन पर महात्मा गाँधी की हत्या में शामिल होने का मुकदमा चला था, हत्यारे नाथूराम गोडसे के पथप्रदर्शक) को शामिल करना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार की योजना डॉ. अंबेडकर की शिक्षाओं को विद्यार्थियों तक पहुँचाने की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबासाहब ने तीन शब्द दिए थे–स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा.. लेकिन देश में अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है। कोई समानता नहीं है। कोई भाईचारा नहीं है। वे एक को देशभक्त कहते हैं और दूसरे को राष्ट्रविरोधी, एक को कश्मीरी दूसरे को गैर कश्मीरी, एक को जेएनयू वाला और दूसरे को गैर जेएनयू वाला। आखिर सिर्फ डा. अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहना देने से भाईचारा कैसे बनेगा।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के तेजस्वी शोध छात्र रोहित वेमुला को 'छात्रों के बीच डॉ. अंबेडकर की बात करने के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार के दो मंत्री सीधे जिम्मेदार हैं जिन्हें बरख़ास्त किया जाना चाहिए। आख़िर प्रधानमंत्री सांवैधानिक पदों पर बैठे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने रोहित को आत्महत्या के लिए मजबूर किया?

तालकटोरा स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच केजरीवाल ने कहा कि मोदी देश नहीं हैं, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह 'आरक्षण के पक्ष में' हैं तो भाजपा किसको 'बेवकूफ' बना रही है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी सरकार को गरीबों और दलितों की सरकार बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्कूलों के पाठ्यक्रम में 'सावरकर' को शामिल करना चाहती है जबकि दिल्ली सरकार की योजना अंबेडकर की 'शिक्षाएं' देने की है। ■

प्रो.थोराट और डॉ. राजशेखर को 'अबंडेकर रत्न' सम्मान

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित दलित उत्थान समारोह में शिक्षाविद और अर्थशास्त्री प्रो. सुखदेव थोराट और यूआईडी के उपमहानिदेशक डॉ. राजशेखर को दिल्ली सरकार के प्रतिष्ठित अम्बेडकर रत्न सम्मान से सम्मानित किया।

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से दलित उत्थान के क्षेत्र में दिये जाने वाले इस सम्मान के रूप में एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

इस मौके पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल, उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, कला एवं भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा के अलावा दिल्ली के विधायक और बड़ी संख्या में दलित उत्थान संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे।

भगत सिंह की याद में दिल्ली में हर साल होगा साहित्य महोत्सव

दिल्ली की गलियों तक पहुँचे साहित्य-केजरीवाल

मशहूर कथाकार असग़र वजाहत को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान

यूँ तो दिल्ली में तमाम मेले लगते हैं, लेकिन दिल्ली हिंदी अकादमी ने इस साल एक अनूठा मेला लगाकर नई शुरूआत की। 23 मार्च को शहीद–ए–आज़म भगत सिंह का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में उनके नाम पर अकादमी ने एक साहित्य महोत्सव आयोजित किया। 25 से 27 मार्च के बीच राजघाट में आयोजित इस मेले में भगत सिंह के सिद्धांतों और सपनों से जुड़ाव रखने वाले साहित्य पर विस्तार से चर्चा हुई और तमाम प्रतिबद्ध साहित्याकरों और समाजसेवियों को सम्मानित भी किया गया।

अकादमी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 मार्च को आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि उनकी सरकार का सपना है कि दिल्ली की गली–गली में साहित्य के आयोजन हों ताकि आम लोगों से साहित्य और साहित्यकारों का सीधा संवाद हो। उन्होंने साहित्यकारों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पुरस्कार वापसी के दौर में हिन्दी अकादमी के पुरस्कारों की इतनी बड़ी स्वीकृति खुशी का विषय है। यह लेखको, संस्कृतियों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार के लंबे रिश्ते की शुरूआत है। सरकार संस्थाओं की स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मशहूर लेखक असगर वजाहत को हिंदी अकादमी का सर्वोच्च शलाका सम्मान प्रदान किया। सम्मान स्वरूप उन्हें 5 लाख रुपए का चेक, शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। वरिष्ठ लेखिका राजी सेठ को शिखर सम्मान और सोनी सोरी को संतोष कोली स्मृति सम्मान से नवाजा गया। दोनों को सम्मान के रूप में 2–2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर कंवल भारती (विशिष्ट योगदान सम्मान), असद जैदी (काव्य सम्मान), अनुपम मिश्र (गद्य विधा सम्मान), देवेंद्र मेवाड़ी (ज्ञान–प्रौद्योगिकी सम्मान), दीपचंद निर्मोही (बाल साहित्य सम्मान), जयदेव तनेजा (नाटक सम्मान), अलका पाठक (हास्य व्यंग्य सम्मान),

अमृत मेहता (अनुवाद सम्मान), ओम थानवी (पत्रकारिता सम्मान–प्रिंट), प्रियदर्शन (पत्रकारिता सम्मान, इलैक्ट्रॉनिक), विमल थोराट (हिन्दी सेवा सम्मान) और मालचंद तिवाड़ी (सहभाषा सम्मान) को भी सम्मानित किया गया। सभी को पुरस्कार स्वरूप 1–1 लाख रुपए का चैक प्रदान किया गया।

दिल्ली के कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने महोत्सव के पहले दिन 25 मार्च को साहित्य प्रेमियों को आश्वस्त किया कि हिन्दी अकादमी हर साल शहीद भगत सिंह साहित्य महोत्सव का आयोजन करेगी। अकादमी की उपाध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा ने संतोष जताया कि हिन्दी अकादमी से सभी तरह के लेखक जुड़ रहे हैं। इस समय अकादमी के पुरस्कारों की स्वीकृति बढ़ी है। अकादमी के सचिव जीतराम भट्ट ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी अकादमी दिल्ली की गली–गली में पहुंच गयी है। शहीद भगत सिंह साहित्य महोत्सव के संयोजक विकास नारायण राय ने कहा कि यह आयोजन आम जनता से जुड़ने का उपक्रम है।

साहित्य महोत्सव में तीनों दिन जनता की रुचिपूर्ण भागीदारी नजर आई। महोत्सव के मैदान में तमाम परिचर्चाएं और नाटक, गीत, संगीत से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन एक साथ हो रहा था। प्रख्यात इतिहासकार प्रो. लालबहादुर वर्मा ने ''भगत कथा'' सुनाई। 'भगत सिंह आज' विषय पर लाल बहादुर वर्मा, प्रताप सहगल एवं एस. इरफान हबीब ने आशीष कंधवे के संयोजन में जोरदार परिचर्चा की। अस्मिता थियेटर ग्रुप ने अरविंद गौड़ के निर्देशन में स्वदेश दीपक लिखित नाटक 'कोर्ट मार्शल' का मंचन किया। महोत्सव में 26 मार्च को पत्रकार

भाषा सिंह के संयोजन में मैत्रेयी पुष्पा, सोना चौधरी और मनीषा ने 'स्त्री आज विषय पर परिचर्चा की।

शीबा असलम फहमी के संयोजन में ओम थानवी, प्रियदर्शन, सोमा चौधरी और वृंदा ग्रोवर के साथ दर्शकों ने पत्रकारिता पर आयोजित बहस में हिस्सेदारी की। वक्ताओं ने कहा कि 900 चैनल और 800 अखबार मिलकर भी एक सौ तीस करोड़ लोगों की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। आज मीडिया देश की जिस अर्थव्यवस्था को प्रमोट कर रहा है, उसमें 94 प्रतिशत जनता की भागीदारी नहीं है।

कविता पाठ के सत्र में सविता सिंह की अध्यक्षता में 13 कवियों ने अपनी कवितायें पढ़ीं। वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल, दिनेश कुमार शुक्ल, विजय किशोर मानव, लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, ज्ञान प्रकाश विवेक, ओम निश्चल, लीना मल्होत्रा, अनुज लुगुन, शायक आलोक, निखिल आनंद गिरि, रश्मि भारद्वाज और प्रकृति करगेती ने अपनी कविताओं का पाठ किया।

लघुकथा सत्र में दस कथाकारों ने अपनी कहानियों का पाठ किया। अशोक भाटिया के संयोजन में बलराम अग्रवाल, मधुदीप, सुभाष नीरव, शोभा रस्तोगी, अंजु दुआ जैमिनी, बलराम, हीरालाल नागर, रामेश्वर काम्बोज 'हिमांशु' और पूरन सिंह ने कहानी पाठ किया।

समानांतर सत्रों में अजय नावरिया के संयोजन में राष्ट्रीय दलित लेखक संघ और हीरालाल राजस्थानी के संयोजन में दलित लेखक संघ के लेखकों ने कविता पाठ किया। युवा मंच में हिन्दू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, खालसा कॉलेज और जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किये।

शहीद भगत सिंह साहित्य महोत्सव का समापन सुप्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा लिखित और संजीव लखनपाल द्वारा निर्देशित नाटक 'गगन दमामा बाज्यो' के मंचन के साथ हुआ। यह नाटक शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित है। ■

संक्षेप में...

वैट निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा। वार्ड 93 में तैनात एक वैट इंस्पेक्टर एक डीलर से पुनः सत्यापन करने के एवज में 5 हजार रुपये की मांग कर रहा था। जबकि डीलर का पंजीकरण अनुरोध वह पहले ही खारिज कर चुका था। डीलर ने वैट आयुक्त सज्जन सिंह यादव का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि डीलर से लिखित शिकायत प्राप्त होने पर व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया। टीम ने शिकायतकर्ता के साथ वार्ड 93 के कार्यालय का दौरा किया और रिश्वत के रूप में भुगतान की गई धनराशि बरामद कर ली।

कर चोरों पर सख्ती

दिल्ली सरकार ने वैट वसूली से कर राजस्व बढाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों को टैक्स दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। सरकार की नजर ऐसे करोबारियों पर है जो उपभोक्ताओं से वैट वसूल रहे है मगर सरकार को नहीं दे रहे हैं। यह जानकारी दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। व्यापार एवं कर विभाग इस बारे में दिल्ली के विभिन्न बाजारों में अभियान चलाएगा।

दिल्ली में होगी चौतरफा हरियाली

दिल्ली की सड़कों पर चलना अब सुहावना अहसास करायेगा। सरकार सड़कों के किनारे और बीच में घास और पेड़–पौधे लगायेगी। हरियाली योजना का उद्घाटन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए दिल्ली सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। दिल्ली को देश औरी दुनिया के सामने एक आदर्श शहर के रूप में पेश करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

स्कूलों की शिकायत के लिए अलग केंद्र

नर्सरी में ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिला प्रक्रिया में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अलग से शिकायत केन्द्र खोलने का फैसला किया है। अभिभावक शिकायत केन्द्र में विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए शिक्षा विभाग ने ईमेल आईडी भी जारी किया है। ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने में अक्षम अभिभावकों के लिए स्कूल शिकायत केन्द्र का दफ्तर झंडेवालान में जिला शिक्षा कार्यालय से संचालित किया जाएगा।

मोहल्ला पुस्तकालय खुलेंगे

मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर अब मोहल्ला पुस्तकालय भी खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार की हिन्दी अकादमी छोटे पुस्तकालय बनाने की योजना पर काम कर रही है। अकादमी की उपाध्यक्ष और मशहूर लेखिका मैत्रेयी पुष्पा ने बताया कि मोहल्ला सभाओं को आधार बनाकर ही छोटे–छोटे पुस्तकालय शुरू किए जाने की योजना है। इसके तहत पहले चरण में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पुस्तकालय बनाए जाएंगे। यहां खासतौर पर युवाओं की जरूरत की शैक्षिक सामग्री मौजूद रहेगी। साहित्य और समाज से जुड़ी किताबों के अलावा इतिहास, विज्ञान और गणित पर भी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी पत्र–पत्रिकाओं को भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। अकादमी इस ओर ज्यादा ध्यान दे रही कि इन्हें मोहल्ला में ज्ञान–विज्ञान के केन्द्र के तौर पर विकसित किया जाए।

दिल्ली में होंगी 50 हजार नियुक्तियाँ

दिल्ली के अनेक विभागों में लगभग 50 हजार नियुक्तियां की जाएंगी। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार तकनीक की भी मदद लेगी। यह जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने दी। उन्होंने बताया कि डीएसएसएसबी, तकनीकी दिक्क़तों की वजह से पिछले 6 सालों से काम ठीक प्रकार नहीं कर पा रहा था। बोर्ड के कामकाज को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने इसके काम काज की समीक्षा की और कई ठोस कदम उठाए है। एक साल में स्थिति में सुधार हुआ है। आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार तकनीकी सेवाओं के प्रयोग को बढा रही है और इससे इन खाली पदों को तेजी से भरने में काफी मदद मिलेगी।

दिल्ली में शुरू हुई किताबगीरी

दिल्ली सरकार ने 10 मोहल्ला पुस्तकालयों के साथ किताबगीरी अभियान की शुरूआत की गई। इस मौके पर वेस्ट विनोद नगर में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कुल 2800 मोहल्ला पुस्तकालय खोले जाएंगे। दिल्ली में किताबगीरी अभियान की शुरूआत भारत अक्षरा सोशल आर्गनाइजेशन द्वारा की जा रही है। यह संस्था बच्चों को किताबे दान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपमुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसमें हर घर और हर बच्चे की सहभागिता बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार ने बच्चों का पाठ्यक्रम 25 फीसदी तक कम कर दिया है।

दिल्ली सरकार खोलेगी खेल विद्यालय

सिर्फ खेलकूद में अपना करियर संवारने के इच्छुक युवाओं के लिए दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स स्कूल खोलगी। यह जानकारी देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार खेलकूद पर विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाने वाले राजीव गाँधी खेल सम्मान समारोह में श्री सिसोदिया ने कहा अगर कोई छात्र खेलकूद में करियर बनाना चाहता है तो उस पर इतिहास, भूगोल और विज्ञान पढने का दबाव क्यों डाला जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को उनकी मर्जी से करियर संवारने को माकूल अवसर मुहैया कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। ■

ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ !

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ? ਜਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਰੁਸਤ ਰਖਣ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2016–17 ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 46,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 41,129 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ– 'ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2016–17 ਵਿਚ 10,690 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜਟ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ''ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਚੂਨ ਮੈਗਜੀਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਘਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵੈਲਰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ।

ਉਧਰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਸਮੇਤ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟੀ ਵੰਡ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟੀ ਵੰਡ 5,908 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5,999 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਗਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ।

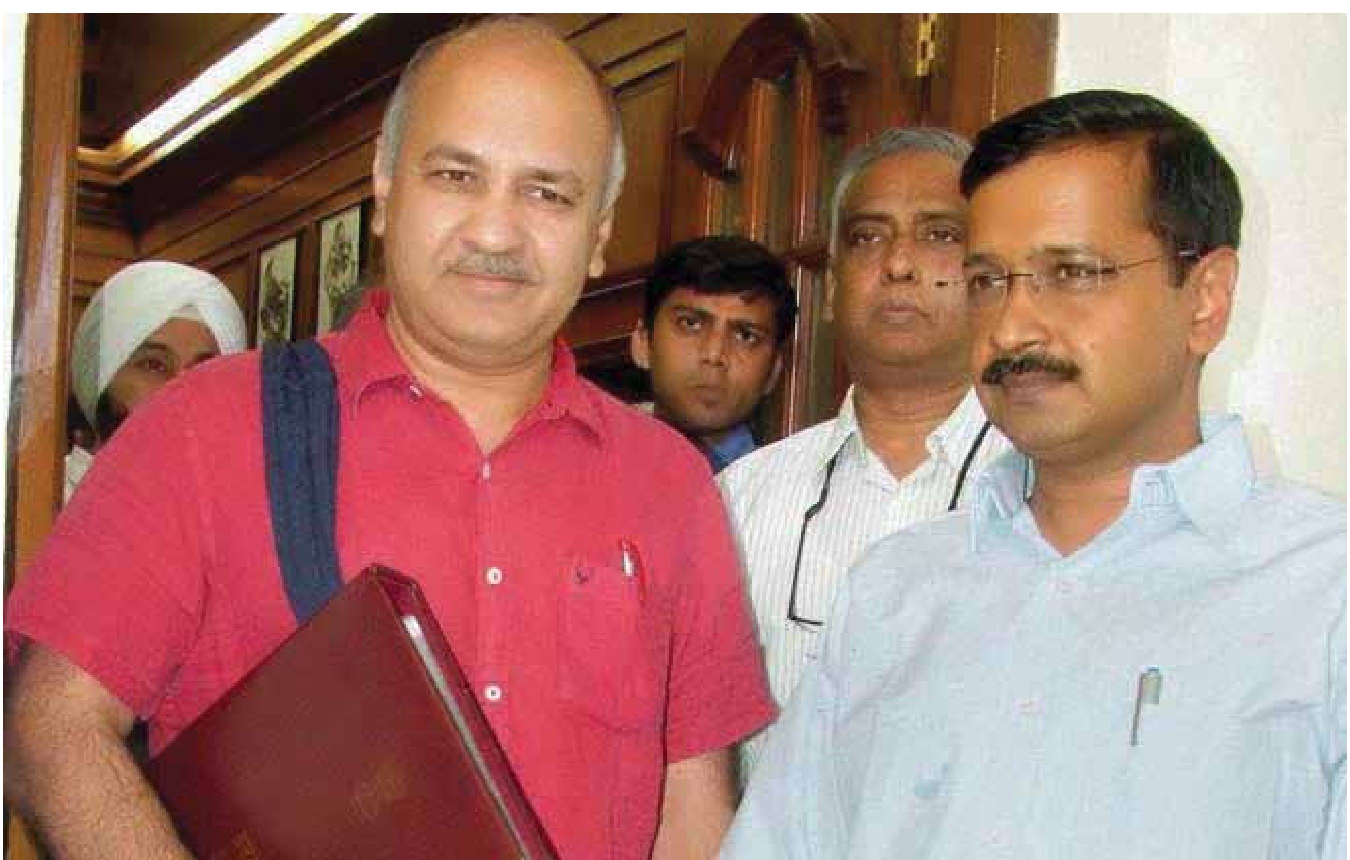

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ 10 ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

1 ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ 5908 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6919 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਮਿਲਣਗੇ।

3 ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4 ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਨਮਕੀਨ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੇਂਟ, ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੇ ਵੀ ਵੈਟ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5 ਸਵਰਾਜ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3000 ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

6 ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਸਵਾਸਥ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲ 10,690 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 1000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਰੰਤ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਗੇ। 150 ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਯੋਜਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।

7 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪੈ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ।

8 ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

9 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ।

10 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ 1000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 248 ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਫੀਡਰ ਬਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਲਈ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਿਹਰਾ ਡੋਜ਼ !

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। 2016–17 ਦੇ ਲਈ ਕੁਲ ਸਵਾਸਥ ਬਜਟ 5,259 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3200 ਕਰੋੜ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 410 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਿਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਬਚੇਗਾ ਹੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਵਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸੇ 1000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ 22 ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਕੁਲ 150 ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਛੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣਾ ਮਰੀਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ– ਮੁਸਕਰਾਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ !

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋੜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਮਰੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ 8000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜੋ 200 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 21 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ 42 ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ-ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਰਖਰਖਾਅ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ-ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵਰਡ, ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਵਲ 9.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਬਜਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9623 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਖੇਡ ਤੇ ਧਿਆਨ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ 55 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਟੇਨਿਸ ਕੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ 205 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2006 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਅਪ੍ਰੇਟਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਧੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਸਟਡੀਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚਾਰੀਆ ਨਰੇਂਦਰਦੇਵ, ਭਗਿਨੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ 2016-17 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਏ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ !

ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਲਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ 88.98 ਰਿ ਜਦ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 86.67 ਫੀਸਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧਾਉ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

'ਐਲੀਵੇਟੇਡ ਕਾਰੀਡੋਰ' ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਦਿੱਲੀ

ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਨਾਉਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2208 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਲ ਬਜਟ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਯਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਐਲਿਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਆਈਐਨਏ (ਅਰਵਿੰਦੋ ਮਾਰਗ) ਤਕ ਬਾਰਾਪੂਲਾ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰਾਪੂਲਾ ਨਾਲੇ ਤੇ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਤਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਬੀਆਰਟੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਪੀਰਾਂਗੜੀ ਤਕ (ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਕਾਰੀਡੋਰ) ਇਹ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਬੀਆਰਟੀ ਕਾਰੀਡੋਰ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ (ਨਾਰਥ-ਸਾਊਥ ਕਾਰੀਡੋਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਐਨਐਚ 24 ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੋਦੀ ਰੋਡ ਤਕ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਤੋਂ ਭੋਪੁਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਫਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਨਾਰਥ-ਸਾਊਥ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 11 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਡਿਜਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਗਲਾਸ ਲਿਫਟ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਚਯਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥ ਵੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ■

ਮੁਹੱਲਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42000 ਡਾਰਕ ਸਪਾਟਸ (ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ) ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 1068 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੇਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 421 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 42000 ਡਾਰਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2016-17 ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ■

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 200 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਵਿਚ 4000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈਫਾਈ, ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦਿਲ ਸੇ, ਆਡ-ਈਵਨ ਫਿਰ ਸੇ !

ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ 15–30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਈਮਾਨੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਟਾਉਣ, ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਚਲਣ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਡ-ਈਵਨ ਦਾ ਵਿੰਟਰ (ਸਰਦੀ) ਅਤੇ ਸਮਰ (ਗਰਮੀ), ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੜਚਨ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਟੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ।

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵਿਚ 50× ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 400 ਤੋਂ 500 ਬਸਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 200 ਤਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੇਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਟੀਸੀ ਬਸਾਂ ਨੇ 35362 ਫੇਰੇ ਲਗਾਏ ਲੇਕਿਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 42,003 ਹੋ ਗਈ। ਡੀਟੀਸੀ ਬਸਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 41,11,327 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 38,58,426 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਟ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ-ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਚ ਹੋਣ।

ਆਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣਾ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ।

ਆਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਿਆ

ਆਡ-ਈਵਨ ਪਾਰਟ-2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ (ਸਫਰ) ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2016 ਦੀ 17 ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਦਾ ਪਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਤਰ ਦਿਨ ਪੀਐਮ 2.5 ਦਾ ਪਧਰ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮ-ਵਿਸ਼ਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਤੋਂ ਨੌ ਦੇ ਵਿਚ। ਰਸ਼ ਆਵਰ। ਨੇਹਾ, 24, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ, ਤੀਨਮੂਰਤੀ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ, ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਰੋਡ, ਤੀਸਹਜਾਰੀ, ਆਈਐਸਬੀਟੀ, ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਹਾ 24। ਯਾਨੀ ਬਿਜੀ ਰਸਤੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ। ਦਮਘੋਟੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ।

ਹੇ ਵਿਜੈ ਗੋਯਲੋ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੇਗੀ? ਦਰ ਚਿਰਕੁਟ ਸਮਝ ਰਖਿਆ ਹੈ?

(26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ)

ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਡੇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀਟੀਸੀ, ਡੀਐਮਆਰਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾ ਲਿਆ। ਡੇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹੈਡ ਵੀ ਸਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਧਰ, ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਮਯੂਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਹਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝੂਤਿਯਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੂਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ

ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 25 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਧਰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ 55 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ।

ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੁਟ ਦੀ ਛੋਟ !

ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਲਾ ਅਤੇ ਓਬੇਰ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਜਿੰਗ (ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਮ ਵਧਾਉਣ) ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁਟ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੰਨਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲੜਾ ਭਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਥ-ਪੈਰ ਢੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਇਕੋਨਾਮੀ ਟੈਕਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ-ਪਾਲੀ ਟੈਕਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਜਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਆਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਦੀ ਛੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ■

ہے۔جھوئن نے کہا کہ دہلی کی خوداعتمادی دیکھ کر وہ متاثر ہوئے ہیں۔دہلی میں جہاں 25لاکھ کاریں ہیں وہیں بیجنگ میں 55 لاکھ کاریں ہیں۔

سرج پرائزنگ کے نام پرنہیں ملی لوٹ کی چھوٹ

آڈ-ایون اسکیم کے لاگو ہونے کے دوران اولا اور اوبیر جیسی ٹیکسی خدمات نے سرج پرائزنگ (مانگ بڑھانے کے ساتھ دام بڑھانے) کے نام پرکرائے میں بھاری اضافہ کردی۔وزیراعلیٰ جناب کیجریوال نے اسے دن دہاڑے لوٹ بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار بلیک میلنگ برداشت نہیں کریگی۔

وزیراعلیٰ جناب کیجریوال نے کہا کہ کچھ ٹیکسی والوں نے کہا ہے کہ اگرانہیں منمانی کرائے وصولنے کا حق نہیں دیا گیا تو ٹیکسی سپلائی نہیں کریں گے۔ایسے ٹیکسی والوں کو دہلی سرکار سخت سبق سکھائے گی۔ان کے لائسنس منسوخ کر دیئے جائیں گے۔

سرکار کی سختی کو دیکھتے ہوئے موجودہ کرایہ سے تین گنا کرایہ وصولنے کی سازش کر رہی کمپنیوں کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔انہیں سمجھ میں آ گیا کہ سرکار ان کی دال گلنے نہیں دے گی۔آڈ-ایون اسکیم کے دوران دہلی کے عوام کو عام دنوں کے حساب سے ہی ٹیکسی کرائے کی ادائیگی کرنا پڑا۔

اسی کے ساتھ سرکار نے ایپ مقررہ ٹیکسیوں کیلئے نئی پالیسی بنانا طے کیا ہے۔اس کے مطابق ٹیکسی والوں کو ٹرانسپورٹ محکمہ کے ذریعے مقررہ کرایہ وصولنے کی اجازت ہوگی۔راجدھانی میں چلنے والی سبھی ایپ مقررہ ٹیکسیوں کیلئے یہ پالیسی لاگو ہوگی۔بھلے ہی وہ ریڈیو،اکنامی ٹیکسی ہو یا کالی پیلی ٹیکسی ،کرایہ طے حساب سے ہی لینا ہوگا۔

ایپ مقررہ ٹیکسی سروس دینے والوں کو لگا تھا کہ سرج پرائزنگ پر سرکار صرف آڈ-ایون کے دوران ہی روک لگا ئیگی۔لیکن حکومت نے صاف کردیا ہے کہ انہیں لوٹ کی چھوٹ کبھی نہیں دی جائیگی۔

کون کھتاھے آڈ-ایوان کامیاب نہیں ھے ؟
آج لگ بھگ 80 کلومیٹر گاڑی چلائی۔شام 4سے 9کے بیچ -بھیڑ کا وقت، نیہا 24 انڈیا گیٹ ،اکبر روڈ ، تین مورتی ، رنگ روڈ ،پنجابی باغ ، پچھم وھا ر،آزاد پور روڈ ، تیس ھزاری ،آئی ایس بی ٹی ، گیتا کالونی روڈ اور پھر نیہا 24 یعنی مصروف راستے جیسے کوئی دوسرا شھر ھو یا اتوار ھو کوئی جام نہیں، دم گھٹنے والے آلودگی نہیں۔ ھے وجے گوئیلوں ،پپو یادو ،تم اپنی نوابی کیلئے دھلی والو ں کا صاف ھوا میں جینے کاحق چھین لینا چاھتے ھو تو عوام وطن پرستی کے نام پر تمھار ا زندہ باد کرے گی ؟ د ر چر کوٹ سمجھ رکھا ھے ؟
(26اپریل کو دھلی یونیورسٹی کے استادکاآشوتوش کمار کے فیس بک پر تبصرہ)

سفر کا دعویٰ ہے کہ آڈ-ایون اسکیم کے لاگو ہونے کے بعد ایک دن بھی آلودگی کا معیار خطرناک درجے میں نہیں پہنچا۔

دھلی سے سبق لیں گے ماسکواور بیجنگ

دہلی کی آڈ-ایون اسکیم کی کامیابی نے پوری دنیا کا دھیان اپنی جانب کھینچا ہے ۔ جام اور آلودگی سے جدوجہد کررہے دنیا کے تمام مشہور شہر دہلی کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں کی کامیابی کو اپنے یہاں دہرانا چاہتے ہیں۔

روس کی راجدھانی ماسکو سے آئے ایک وفد نے 26 اپریل کو اس سلسلے میں دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ گوپال رائے سے ان کے دفتر میں ملاقات کی دہلی سرکار نے وفد کو دہلی میں اس یوجنا کو لاگو کرنے اور کامیاب بنانے کی جانب میں اٹھائے گئے قدموں کی جانکاری دی۔ میٹنگ میں ڈی ٹی سی ،ڈی ایم آر سی ، پولیس آفیسروں نے بھی حصہ لیا۔ وفد نے ماسکو کے میئر ، ٹرانسپورٹر ڈپارٹمنٹ کے افسر اور ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے ڈپٹی ہیڈ بھی تھے۔

وفد اس بات سے کافی متاثر ہوئے کہ دہلی کا سارا پبلک ٹرانسپورٹ سی این جی پر منحصر ہے۔ وفد کے ممبران نے دہلی سرکار کی نقل وحمل انتظام سے جڑی تمام یوجناؤں میں دلچسپی دکھائی تاکہ ماسکو کو بھی نئی راہ مل سکے۔

اُدھر، چین پہلے دہلی سرکار کی آڈ-ایون یوجنا کی تعریف کرچکا ہے۔ چین کی راجدھانی بیجنگ کے میونسپل کمیشن نے ٹرانسپورٹ کے کمشنر جھو تیان کے مطابق نمبر قانون دہلی کے آلودگی کو دور کرنے اور نقل وحمل انتظام کو درست کرنے میں مددگار ثابت ہورہا ہے۔ اسکا مستقبل میں اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر اسے لمبے وقت تک معقول طریقے سے لاگو کیا جائے۔ غور طلب ہے کہ نمبر اسکیم سب سے پہلے چین کے بیجنگ میں شروع کی گئی تھی لیکن کامیابی نہیں ملی تھی اب دوبارہ وہاں اس یوجنا کو شروع کیا جاسکتا

پاس آڈ-ایون کا ونٹر (سردی) اور سمر (گرمی) دونوں ماڈل ہیں۔دونوں ماڈلوں کا انتخاب کر کے آگے کی یوجنا بنائی جائے گی۔

وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ اس یوجنا کو ناکام بنانے کیلئے سیاسی مداخلت کی گئی۔آٹو ہڑتال کرنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن سرکار نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔انھوں نے کہا کہ کچھ جگہوں پر جام کی شکایت آئی لیکن ایسا مقامی سطح پر چل رہے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے نہ کہ ڈی ٹی سی بسوں بریک ڈاؤن سے۔

انہوں نے بتایا کہ ڈی ٹی سی بسوں بریک ڈاؤن میں 50 فیصد کی کمی آئی۔اس شدید گرمی میں پہلے 400 سے 500 بسوں کا بریک ڈاؤن ہوتا تھا، جو آڈ-ایون کے دوران گھٹ کر 200 تک رہ گیا ہے۔ساتھ ہی ان میں سے زیادہ تر بسوں کو 20 سے 35 منٹ کے اندر اٹینڈ کر لیا جاتا تھا۔اس کے چلتے جام کی حالت نہیں ہو رہی ہے۔ان بسوں میں چلنے والوں کی تعداد میں بھاری اضافہ ہو،انھوں نے مثال دیا کہ آڈ-ایون سے پہلے 11 اپریل کو یہ تعداد 42003 ہوگئی۔ڈی ٹی سی بسوں 18 اپریل کو 4111327 لوگوں نے سفر کیا۔11 اپریل کو 3856426 لوگوں نے سفر کیا تھا۔

پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کچھ خاص لوگوں کو چھوٹ دی گئی۔صدر، نائب صدر، وزیر اعظم، بھارت کے چیف جسٹس، مرکزی وزیر اور دہلی کے علاوہ باقی دیگر صوبوں اور مرکز کے ماتحت صوبوں کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی گاڑیوں کو اس قانون سے چھوٹ ملی۔حالانکہ دہلی کے وزیر اعلیٰ جناب اروند کیجریوال وان کی کابینی وزراء میں شامل وزیر اس چھوٹ کے دائرے میں نہیں تھے۔بیٹری اور رجسٹرڈ ایجنسیوں کے ذریعہ لگائی گئی سی این جی کٹ سے چلنے والی کاروں پر یہ قانون لاگو نہیں تھا ساتھ ہی دو پہیہ گاڑی ڈرائیوروں کو شامل نہیں کیا گیا۔ایمبولینس، محکمہ فائر بریگیڈ، پولیس گاڑی، محکمہ ٹرانسپورٹ، کی گاڑیوں کو بھی چھوٹ تھی۔تنہا خاتون کے اسکول چھوڑنے، لانے کیلئے سرپرستوں کو چھوٹ دی گئی بشرطیکہ بچہ اسکولی ڈریس میں ہو۔

آڈ-ایون کے دوران لاکھوں گاڑیوں کے سڑک پر نہ اترنے سے آلودگی میں کمی فطرتاً تھی۔اس کے علاوہ جام کے بنا دہلی کی سڑکوں پر چلنا سفر سنہرا بنا رہا تھا جو ایک ناممکن سپنے کی طرح تھا۔

آڈ-ایون کے دوران آلودگی گھٹی

آڈ-ایون کے دوسرے مرحلے کے دوران دہلی میں فضائی آلودگی میں کمی آئی۔سسٹم آف ایئر کوالٹی اینڈ ودر فورکاسٹنگ اینڈ ریسرچ (سفر) کی مونیٹرینگ سے پتہ چلا ہے کہ 2015 کے مقابلے میں 2016 کی 17 سے 26 اپریل کے بیچ پی ایم 2.5 کا معیار کم رہا۔وہیں زیادہ تر دن پی ایم 2.5 کا معیار معمول کے آس پاس ہی رہا۔

دلّی بولی دل سے، آڈ۔ایون پھر سے!

کامیاب رہا 15-30 اپریل کا دوسرا مرحلہ

دلّی کی عوام نے آڈ۔ایون اسکیم کو ایک بار پھر کامیاب بنا کر ثابت کردیا کہ اگر سیاسی رہنمائی کے ارادوں میں ایماندار ہو تو جنتا تعاون دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہتی۔جنوری کے کامیاب تجربہ کے بعد اپریل مہینے کی 15 سے 30 اپریل کے بیچ اس تجربہ کو دوہرایا گیا اور نتیجوں نے ثابت کیا کہ آلودگی ہٹانے جام سے نجات دلانے اور لوگوں میں تعاون کا احساس ترقی یافتہ کرنے کا مقصد کافی حد تک پورا ہوا۔وزیراعلیٰ جناب کیجریوال نے اس اسکیم کی کامیابی کیلئے دہلی کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔

اس بار آڈ۔ایون کی کامیابی کو لیکر شبہ کے دو مدعے تھے ایک تو پچھلی بار کی طرح اس بار اسکول بند نہیں تھے، دوسرے یہ بھی کہا جارہا تھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ نجی گاڑیوں سے چلنے کا ضد نہیں چھوڑ پائیں گے۔لیکن عوام نے سارے اندیشوں کو ثابت کرتے ہوئے اس منصوبہ کو کامیاب بنایا۔وزیر نقل وحمل گوپال رائے نے کہا ہے کہ جب دہلی کے

محلہ محافظ فورس کریگی

خواتین کی حفاظت

عام آدمی پارٹی کی سرکار نے خواتین کی تحفظ کو ہمیشہ اولیت دی ہے۔اس بجٹ میں بھی اس کی جھلک دکھی جب سرکار نے محلّہ محافظ فورس کی تشکیل کیلئے 200 کروڑ روپے کا بندوبست کیا۔سرکار کے مطابق 2016-17 میں سبھی ودھان سبھا علاقوں میں محلّہ محافظ فورس تشکیل دینے کی یوجنا ہے۔اس کے علاوہ سرکا نے 42000 اندھیرے گوشے (اندھیرے کونوں) کی پہچان کی ہے۔جنہیں جلدی ہی روشنی کے انتظام سے جوڑ دیا جائے گا۔خواتین کی تحفظ اور ان کو تفویض با اختیار بنانے کیلئے سرکار نے بجٹ میں 1068 کروڑ روپے کا بندوست کیا ہے۔سرکار نے کراول نگر ودھان سبھا حلقہ میں سول ڈیفنس والینٹرس کو لیکر محلّہ محافظ فورس بنایا تھا جس پر اچھا ردِعمل ملا۔اسے دیکھتے ہوئے اب سبھی اسمبلی حلقوں میں محلّہ محافظ فورس تشکیل کئے جائیں گے۔اس کیلئے سرکار نے 200 کروڑ روپے کا بندوبست ہے۔

نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے بتایا کہ دہلی پولیس، کچھ این جی او اور دیگر ایجنسیوں کی مدد سے سرکار نے 421 سڑکوں پر 42000 اندھیرے گوشے کو نشاندہی کیا ہے۔ان جگہوں پر خواتین کی حفاظت کو خطرہ رہتا ہے۔114 کروڑ روپے خرچ کرنے ان جگہوں پر لائٹ کا انتظام کیا جارہا ہے۔2016-17 تک یہ کام پورا کرلیا جائیگا۔

سی سی ٹی وی کیلئے 200 کروڑ

سرکار نے سی سی ٹی لگانے کیلئے 200 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے سرکار کے مطابق ڈی ٹی سی کی 200 بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا چکے ہیں۔کچھ بسوں میں مفت وائی فائی سہولیت بھی شروع کی جا چکی ہے اور بسوں میں 4000 مارشل بھی تعینات کئے گئے ہیں۔سرکار کے مطابق سبھی ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسوں میں وائی فائی، جی پی ایس اور سی سی ٹی وی لگانے کا بندوبست ہے۔

سرکار کے مطابق جواہر لال نہرو اسٹیڈیم سے آئی این اے (اروندو مارگ) تک بارہ پولا نالا پر ایلی ویٹیڈ روڈ کا دوسرا مرحلہ اسی سال پورا ہوجائیگا۔ بارہ پولا نالا پر 1261 کروڑ روپے لاگت والے سرائے کالے خاں سے میور وہار تک ایلی ویٹیڈ روڈ کے تیسرے مرحلے کی تعمیر دسمبر تک پوری ہوجائے گی۔ دونوں پروجیکٹوں پر 400 کروڑ روپے خرچ کرنے کا بندوبست ہے۔

اسی کے ساتھ سرکار نے ایلی ویٹیڈ روڈ کے سفر کو میٹرو کی طرز پر آرام دہ بنانے کی یوجنا بنائی ہے۔ سرکار دو ایلی ویٹیڈ بی آر ٹی کوری ڈور بنانے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے۔ ایک کوری ڈور آنند وہار ٹرمینل سے پیرا گڑھی تک (ایسٹ ویسٹ کوری ڈور) ہوگا۔ یہ 29 کلومیٹر کا ہوگا۔ دوسرا ایلی ویٹیڈ بی آر ٹی کوری ڈور 29 کلو میٹر کا (نارتھ ساؤتھ کوری ڈور) ہوگا۔ یہ وزیر آباد سے ایئر پورٹ تک بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی دیگر چار مارگوں پر ایلی ویٹیڈ کوری ڈور، این ایچ 24 بائی پاس سے لودھی روڈ تک ایک انڈر گراؤنڈ سرنگ اور کھجوری خاص سے بھوپرا بارڈر تک کوری ڈور کی فیزی بلیٹی ایس ٹی ڈی کرائی جا رہی ہے۔ ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ ماڈل کو پوری دہلی میں لاگو کیا جائیگا۔

نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے مطابق دہلی کی 11 سڑکوں کو ری ڈیزائن کیا جائے گا تاکہ پیدل اور سائیکل مسافروں کے لئے بھی مناسب جگہ ہو۔ نئے ڈیزائن کی سڑکوں میں گلاس لفٹ، اسٹریٹ لائٹ اور بارش کا پانی جمع کرنے کیلئے انتظام کئے جائیں گے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر وکاس پوری سے وزیر آباد کی 20 کلومیٹر سڑک کے دونوں جانب سائیکل ٹریک اور فٹ پاتھ بھی بنانے کی تجویز ہے۔

دھلی میں میٹرو کی طرز پر ہوگا زمینی ٹرانسپورٹ!

’ایلیویٹیڈ کوریڈور‘ سے جڑے گی دھلی

بڑھتی آبادی اور گاڑیوں کے بوجھ نے دہلی کی سڑکوں پر برا اثر ڈالا ہے۔آئے دن جام کی اور آلودگی کی پریشانی سے نمٹنے کیلئے کیجریوال سرکار کے طاق - جفت استعمال کو عوام نے سراہا تو ہے، لیکن کئی اور مورچوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔اس کیلئے دہلی سرکار نے ایلیویٹیڈ کوریڈور بنانے کی آرزومندی یوجنا تیار کی ہے۔

دہلی سرکار نے راجدھانی کے زمینی ٹرانسپورٹ کو درست کرنے کیلئے 2208 کروڑ روپئے کا یوجنا بجٹ بنایا ہے جو کل بجٹ کا 11 فیصدی ہے۔وزیراعلیٰ کیجریوال نے بتایا کہ پائلیٹ یوجنا کے تحت 2 ایلی ویٹیڈ کوریڈور بنانے کی اہم یوجنا پر کام شروع ہوگیا ہے۔اگر ہوائی سڑکوں کے ذریعہ دہلی کی دوریوں کو ناپنے کی یوجنا کامیاب رہی تو سڑکوں پر جام اور آلودگی سے راحت ملے گی۔

ووکیشنل ٹریننگ - دہلی کے 205 اسکولوں میں ووکیشنل ٹریننگ شروع کردی گئی ہے اب سبھی اسکولوں میں ایسا کرنے کیلئے 105 کروڑ روپے کا بجٹ منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ 2006 میں بند کی گئی اسٹیٹ اپرینٹس شپ پروگرام سرکار پھر شروع کریگی۔ کم ازکم 50 ہزار نوجوانوں کو اسکل ٹریننگ دینے کا مقصد ہے۔

اعلیٰ تعلیم- سرکار اعلیٰ تعلیم میں سدھار کیلئے قدم اٹھا رہی ہے اس کے تحت امبیڈکر یونیورسٹی کے روہنی اور دھیر پور میں نئے کیمپس شروع ہوں گے دین دیال اپادھیائے کالج اور شہید سکھ دیو کالج آف بزنس اسٹڈیز کو نئی عمارت میں تبدیل کیا جائے گا۔ آچاریہ نریندر دیو، بھگینی نویدتا اور گرو گوبند سنگھ آئی پی یونیورسٹی کے کیمپس کی تعمیر بھی 2016-17 میں شروع ہوجائے گی۔

دہلی کے سرکاری اسکول پڑے نجی اسکولوں پر بھاری!

اس بار سی بی ایس ای 12 ویں کے امتحان کے نتیجوں میں دہلی کے سرکاری اسکولوں نے نجی اسکولوں کو نتیجے کے معاملے میں مات دے دی۔ نتیجوں کے مطابق دہلی کے سرکاری اسکولوں کے بچوں کا پاس فیصد 88098 رہا۔ جبکہ نجی اسکولوں میں صرف 86.67 فیصدی۔ دہلی سرکاری اسکولوں میں ایجوکیشن کی خاصیت بڑھانے کیلئے تمام کوشش کررہی ہے جس کا اثر صاف نظر آیا۔ شعبۂ تعلیم کے افسروں اور اساتذہ کی محنت نے ماحول بدلا اور طلباء میں بھی پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ دہلی کے 130 اسکولوں کے نتائج 100 فیصدی رہے۔

دہلی کے نائب وزیراعلیٰ و وزیر تعلیم منیش سسودیا نے اس حصولیابیوں پر خوشی جتاتے ہوئے کہا کہ سرکاری اسکولوں نے نجی اسکولوں سے بہتر نتائج پیش کئے، اس کیلئے دہلی کی ایجوکیشن ٹیم کو مبارکباد، انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کی مجھے ٹیم پر فخر ہے۔ ادھر وزیراعلیٰ اروند کیجریوال نے بھی سرکاری اسکولوں کی اس حصولیابی پر خوشی جتائی۔ انہوں نے اسکولوں میں ٹاپ کرنے والے 4 طلباء سمیت آل انڈیا ٹاپ کرنے والی طالبہ سکرتی گپتا کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دہلی کے نجی اسکولوں پر لوگوں کی منحصریت کم کرنے اور سرکاری اسکولوں کو نجی اسکولوں کی احتیاج بہتر بنانے کی جانب کام کررہی ہے، اسے ان امتحان نتائج سے اور زیادہ زور ملے گا۔ دہلی سرکار نے سرکاری اسکولوں کے سسٹم کو بدلنے کیلئے پچھلے سوا سال سے بڑے قدم اٹھائے ہیں انہی نتیجوں کی جانب یہ نتائج اشارہ کرتے ہیں۔

اورنصاب تعلیم نئے زمانے کے حساب سے ہوں۔ بچوں کو اچھا باشندہ بنانے کا خواب تبھی پورا ہو سکے گا۔ دہلی میں تعلیمی انقلاب لانے کی صدارت کر رہے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کہتے ہیں کہ استاذ- طلباء تناسب ٹھیک کرنے سے لیکر اسکولوں میں پڑھائی کے ماحول کی راہ میں آنے والے ہر روڑے کو سرکار ہٹائیگی۔ انہوں نے اپنے بجٹ خطاب میں 8000 نئے کلاس روم بنانے کا ارادہ جتایا جو 200 نئے اسکولوں کے برابر ہیں۔ ان کمروں کی تعمیر چل رہی ہے۔ اور اگلے جولائی سے یہ کام میں آسکیں گے۔ وزیر تعلیم منیش سسودیا نے بتایا کہ 21 نئے اسکولوں کی بلڈنگ تیار ہو چکی ہیں جن میں ڈبل شفٹ میں 142 اسکول چلائے جاسکتے ہیں۔

اسٹیٹ منیجر۔ بجٹ میں ہر اسکول میں ایک اسٹیٹ منیجر مقرر کرنے کا بندوبست ہے اس کی ذمہ داری اسکول کی عمارت اور کمپلیکس کے رکھ رکھاؤ کی ہوگی اسٹیٹ منیجر اسکول کی حالت کی ویڈیو کلپ روزانہ اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھیجیں گے ۔ پرنسپلوں پر بوجھ گھٹے گا اور پوری طرح پڑھنے پڑھانے کی نگرانی پر دھیان دے پائیں گے۔

اساتذہ کی خوبیاں - بجٹ میں اساتذہ اور پرنسپلوں کو اعلیٰ ترین ٹریننگ دلانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہارورڈ، کیمبرج اور آکسفورڈ جیسے یونیورسیٹیوں میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ باقی دنیا میں ایجوکیشن دنیا کے بدلاؤ کو جان پرکھ سکیں۔ اس کیلئے بجٹ میں 102 کروڑ روپے کا منصوبہ رکھا گیا ہے جبکہ پچھلی بار صرف 9.4 کروڑ کا بجٹ تھا۔ سرکار کے مطابق 5500 استاذوں کی تقرری کی عمل چل رہی ہے۔ عارضی اساتذہ کو پرمانٹ کرنے کی عمل چل رہی ہے اور 9623 نئی آسامیوں کیلئے بھی تشکیل دی جا رہی ہیں۔ اساتذہ کو اب مردم شماری جیسے کاموں میں نہیں لگایا جائیگا تاکہ پڑھائی میں خلل نہ ہو۔

کھیل پر دھیان - کھیلوں کو بڑھاوا دینے کیلئے سرکار نے 48 کروڑ روپے کا بندوبست کیا ہے کھیل تنظیموں کیلئے اسکولوں کے کھیل میدان کھولنے اور 55 اسکولوں میں عالمی سطح کا فٹبال گراؤنڈ اور ٹینس کورٹ تیار کرنے کا منصوبہ ہے۔ بجٹ میں اسپورٹس اسکول اور اسپورٹس یونیورسیٹی کھولنے کا بھی منصوبہ ہے۔

دھلی میں ایجوکیشن کا کایا کلپ !

ملک میں سرکاری ایجوکیشن منیجمنٹ کی بدحالی کارونارونے والوں کیلئے دہلی کی خبریں آرام دہ حیرانی کی طرح ہے کہاں تو سرکاری اسکول کا مطلب بچے کی زندگی سے کھلواڑ مانا جاتا ہے اور کہاں دہلی کے سرکاری اسکول نجی اسکولوں سے ہوڑ لینے میں جٹے ہیں۔کل بجٹ کا تقریباً 24 فیصدی صرف ایجوکیشن پر خرچ کرنے کا اعلان کر کے کیجریوال سرکار نے بتا دیا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ دنیا بھر میں اس انوکھی پہل کی چرچا ہے۔اخباروں میں اداریہ لکھے جارہے ہیں۔

بنیادی خاکہ، استاذ اور نصابِ تعلیم - دہلی سرکار ان تین مسئلوں پر اپنا پورا دھیان دے رہی ہے یعنی اسکول میں کمرے فرنیچر سے لیکر دیگر بنیادی سہولتیں بہتر ہوں۔اساتذہ میں پڑھانے کا جوش ہو۔

دھلی والوں کو صحت کا تیہراڈوز!

دھلی کی کیجریوال سرکار نے صحت خدمات میں بہتری کیلئے پچھلی بار سے ڈیڑھ گنا زیادہ بجٹ دیا ہے۔ یہ کل بجٹ کا16 فیصدی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی صحت کولیکر کتنی فکرمند ہیں۔2016-17 کے کل صحت بجٹ 5259 کروڑ روپے کا ہے۔جس میں سے 3200 کروڑ پلان بجٹ ہے۔

سرکار کی سب سے آرزومند اور اثردار منصوبہ ہے کہ لوگوں کو اسپتالوں میں ہر حال میں مفت دوا ملے۔اس کیلئے سرکار نے 410 کروڑ روپے کا بندوبست کیا ہے۔ بجٹ خطاب کے دوران نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے صاف کہا ہے کہ سرکار کا مقصد صرف انفراسٹرکچر درست کرنا نہیں بلکہ ہیلتھ منیجمنٹ کو بھی درست کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اسکے لئے تین سطحوں والا سسٹم بنانے کی منصوبہ پر کام کررہی ہے جوملک کے کسی بھی صوبے میں نہیں ہوا۔

دراصل دہلی سرکار کا ارادہ ہے کہ عام جنتا اپنی نرسنگ ہوموں یا اسپتالوں کے بیکار چکروں میں بے وجہ نہ پھنسنے پائیں۔اگرلوگوں کو بیماری کی شروعات میں گھر کے پاس ہی جانچ اور علاج کی سہولیات مہیا ہو جائے تو پیسہ اور وقت بچے گا ہی، بیماری بڑھنے بھی نہیں پائے گی۔محلّہ کلینک اسی فکر کی پیداوار ہے جہاں ڈاکٹر دوا اور تمام جانچ کی سہولیت ہوگی۔ پوری دہلی میں ایسے ہزار محلّہ کلینک کھولے جانے ہیں جن میں 100 بہت جلد شروع ہو جائیں گے۔ اس پریوجنا کی تعریف امریکہ سمیت دنیا بھر کے اخباروں میں ہو رہی ہے۔صحت، حفاظت کا دوسرا چکر پولی کلینک کی ہیئت ہوگی۔ جہاں ماہر خصوصی ڈاکٹر اور سبھی قسم کی جانچ کی سہولیت ہوگی۔ اب تک 22 پولی کلینک شروع ہو چکے ہیں۔ اور ایسے میں کل 150 پولی کلینک کا جال پوری دہلی میں بچھے گا۔

تیسرا چکر ہوگا بڑے اسپتالوں کا، جہاں بہت مجبوری میں ہی کسی مریض کو جانا ہوگا سبھی سرکاری اسپتالوں میں مفت دوا پانا مریض کا عوامی حق ہے۔اگرکسی اسپتال میں کوئی خاص دوا موجودنہیں ہے تو پربھاری اسے خودمنگا کر مریض کو دینے کیلئے پابند ہوگا۔

اس کے بعد کون مریض نہیں کہے گا 'مسکرایئے کی دہلی میں کیجریوال سرکار ہے۔

دہلی سرکار کے بجٹ کی 10 خاص باتیں

1 دہلی میں بجلی سبسڈی جاری رہے گی اور اس کیلئے بجٹ میں 1600 کروڑ روپے کا بندوبست کیا گیا ہے۔

2 دہلی کے نگرنگموں کا بجٹ 1000 کروڑ روپے بڑھا دیا گیا ہے یعنی نگموں کو اب سالانہ 5908 کروڑ روپے سے بڑھا کر 6919 کروڑ روپے ملیں گے۔

3 ماحولیات کے مطابق گاڑیوں، بیٹری سے چلنے والی اور ہابریڈ گاڑیوں پر ویٹ کو 12.5% سے گھٹا کر 5% کر دیا گیا ہے۔

4 اس کے علاوہ مٹھائیوں، نمکین، سبھی ریڈی میڈ گارمینٹ، ماربل اور سبھی فٹ ویئر و اسکول بیگ پر بھی ویٹ 12.5% سے گھٹا کر 5% کر دیا گیا ہے۔

5 سوراج ندھی یوجنا میں 350 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اور اب ہر ودھان سبھا میں محلّہ سبھا بنے گا اور اس کا بجٹ بنے گا۔ پوری دہلی میں قریب 3000 محلّہ سبھائیں ہوں گی۔

6 بجٹ کا ایک چوتھائی حصہ ایجوکیشن کیلئے اور 16 فیصدی صحت میدان میں سرمایہ کاری کیا جائیگا۔کل 1069 کروڑ روپے ایجوکیشن منیجمنٹ کو اعلیٰ بنانے کے لئے رکھے گئے ہیں۔ وہیں صحت خدمات سدھارنے کیلئے سال کے آخر تک 1000 محلّہ کلینک کیلئے ٹینڈر جاری کئے جائیں گے۔100 محلّہ کلینک جلد کھولے جائیں گے۔150 پالی کلینک کھولنے کا منصوبہ ہے۔جن میں سے 22 چالو ہو چکے ہیں۔

7 عام آدمی کینٹین کیلئے 10 کروڑ روپے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ دہلی میں کئی جگہ شروع ہونیوالی اس کینٹین میں محض 5 سے 10 روپے میں کھانا ملے گا۔

8 سبھی اسکولوں کے ہر کلاس میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کیلئے 100 کروڑ روپے تقسیم کئے گئے ہیں۔ وزیرخزانہ سسودیا کے مطابق سرکاری اسکول کو پرائیویٹ اسکولوں سے بہتر بنایا جائے گا۔

9 دہلی سرکار کے بجٹ میں شہر میں وائی فائی اور خاص سڑکوں کے ساتھ سائیکل لین بنانے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔

10 دہلی کیلئے 1000 نئی بسیں خریدی جائیں گی۔ ای رکشہ کیلئے 15000 سے بڑھا کر 30000 روپے کر دی گئی ہے۔248 نئے میٹرو فیڈر بسیں آئیں گی۔ میٹرو کیلئے 763 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔

یہ بجٹ ایسا تھا کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ 30 مارچ کو یہ بجٹ ودھان سبھا سے منظور کر دیا گیا۔شروع میں سرکار نے کم قیمت والے فٹو ییئر پانچ فیصدی ٹیکس کی تجویز رکھی گئی تھی لیکن اسے واپس لے لیا گیا۔ اس سے بیوپاریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ودھان سبھا کمپلیکس پہنچ کر سرکار کو مبارکباد دیتے ہوئے جشن منایا۔

ودھان سبھا میں بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اسے تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ منیش سسودیا کے ذریعے پیش کئے گئے بجٹ کی ملک اور دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ''لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسری سرکار میں بھی بجٹ بنانا دہلی سرکار سے سیکھیں۔ ہم اقتدار میں آئے تو کہا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو گورنینس نہیں آتی۔ اب وہ بھی ہم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار ہماری تعریف میں لکھ رہے ہیں۔ فارچیون میگزین نے ہمارا نام دنیا کے 50 بااثر لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔

کم قیمت والے فٹو ییئر اور کپڑوں پر پانچ فیصدی ٹیکس کی تجویز کو واپس لینے کو یوٹرن کہے جانے کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے کسی فیصلے سے عوام کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آدھی رات کو بھی یوٹرن لے لیں گے۔ کسی کا روزگار نہیں چھیننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مرکزی سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ایکسائز ڈیوٹی کے معاملے پر یوٹرن لے اور اپنے انا نیت کو چھوڑ جیولرس کے کاروبار کو بچا لیں۔

وہیں وزیر خزانہ منیش سسودیا نے کہا کہ ان کی سرکار ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے عوام کو پریشانی ہو۔ سرکار نے دوسرے سال کے بجٹ میں بھی ایجوکیشن، صحت اور ٹرانسپورٹ سمیت عوامی فلاح و بہبود یوجناؤں کیلئے رقم منظور کی ہے۔ منیش سسودیا نے کہا کہ راجیہ سرکار نے نگر نگموں کیلئے بجٹ مختص 1000 کروڑ روپے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہلی کے نگر نگموں کیلئے پچھلے سال بجٹ تخصیص 5908 کروڑ روپے تھا۔ بعد میں اسے بڑھا کر 5999 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ اس سال بجٹ میں اسے بڑھا کر 6919 کروڑ روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی ماتحت نگر نگموں کو رقم کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بھی صلاح دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی ایم سی ڈی اس رقم کا استعمال ملازمینوں کو صحیح وقت پر تنخواہ دینے میں کریگی۔

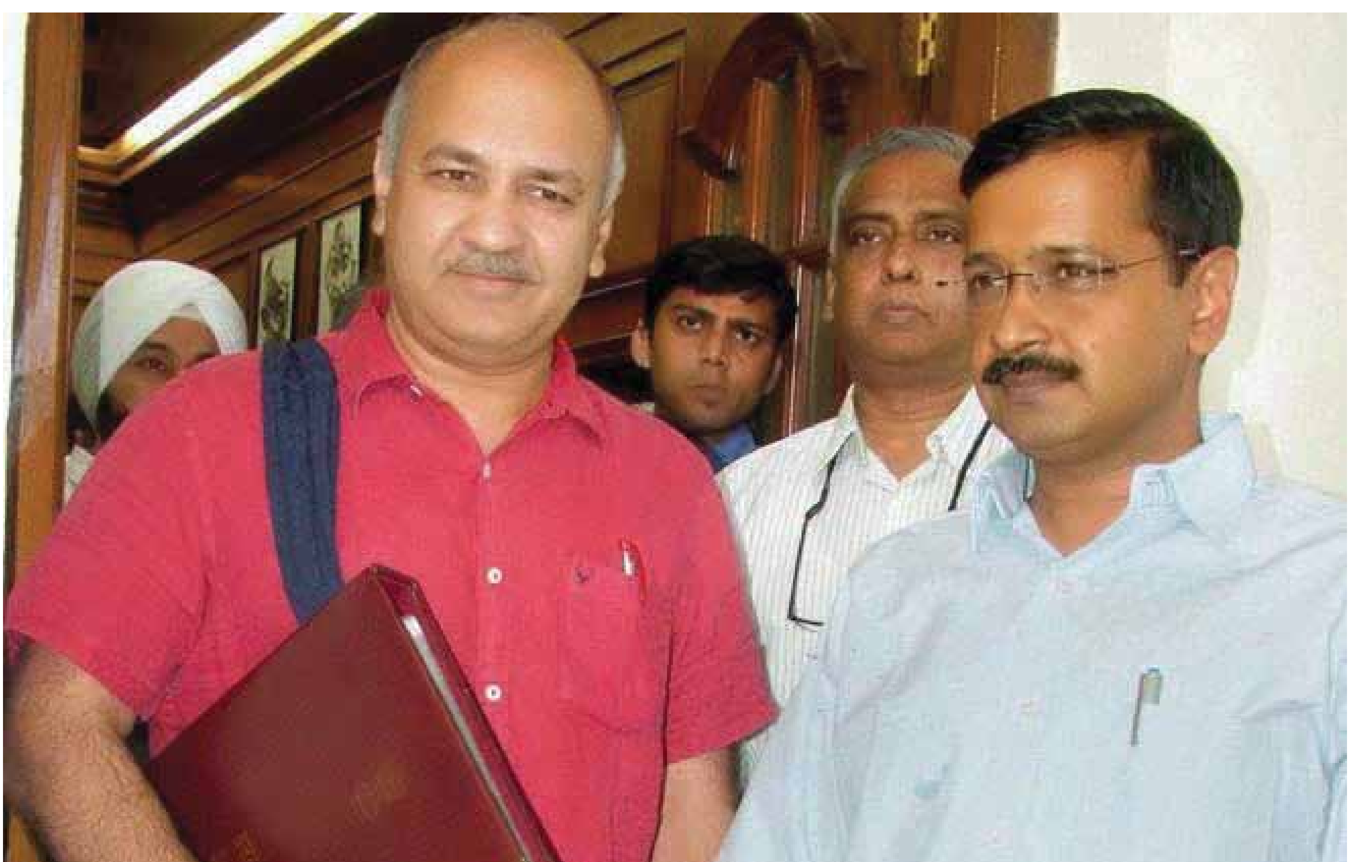

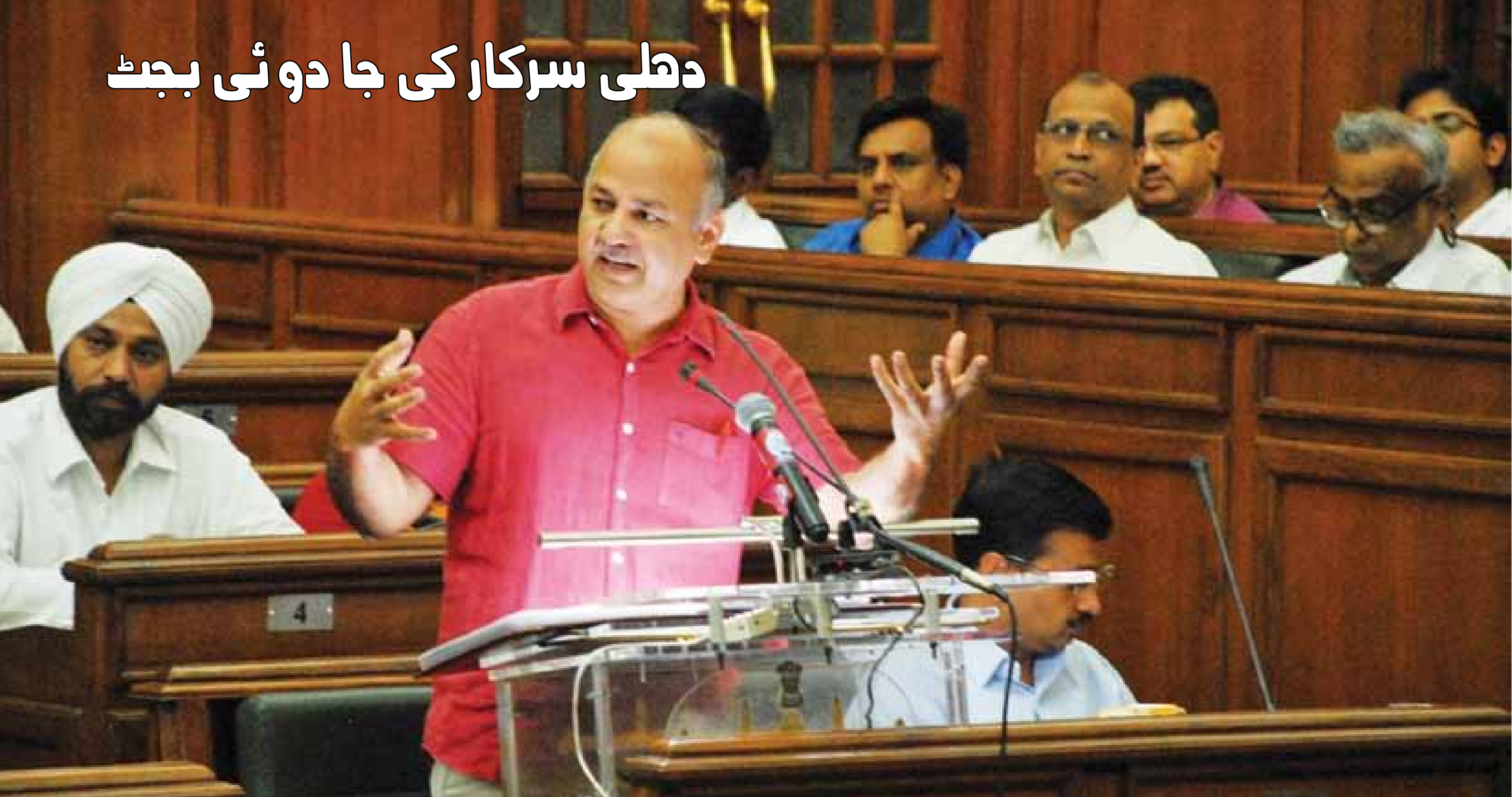

سہولتیں ہزار، پر نہیں ٹیکس کی مار!

کیا آپ نے کبھی سنا کہ کوئی سرکار اپنے بجٹ کا لگ بھگ چوتھائی حصہ ایجوکیشن منیجمنٹ درست کرنے پر خرچ کردے؟ یا خزانے کا 16 فیصدی حصہ لوگوں کی صحت درست رکھنے میں لگا دیں؟ ساتھ ہی نہ کوئی نیا ٹیکس نہ پرانے ٹیکس میں بڑھوتری۔ یہ انوکھی بات ہے لیکن دہلی کی کیجریوال سرکار نے اپنے بجٹ کے ذریعے ایک بار پھر ثابت کیا کہ دہلی کے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔

دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ منیش سسودیا نے 28 مارچ کو ودھان سبھا میں مالی سال 2016-17 کیلئے جب عام آدمی پارٹی کی سرکار کا بجٹ پیش کیا تو نگاہ میں صرف عام آدمی تھا۔ انہوں نے اس بار 46600 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا۔ جب کہ پچھلی بار 41129 کروڑ روپے کا بجٹ پیش ہوا تھا۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے سسودیا نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی اولیت ایجوکیشن اور صحت ہے۔ ایجوکیشن کیلئے سال 2016-17 میں 10690 کروڑ روپے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ ایجوکیشن منیجمنٹ کو کنٹرول کی نہیں، بندوبست کی ضرورت ہے۔

इन्क़लाब! ज़िन्दाबाद!!

23 मार्च को दिल्ली विधानसभा परिसर में शहीद–ए–आज़म भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण हुआ

शहीदों की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर, 1929 में भगत सिंह को दिल्ली में शरण देने वाले 106 वर्षीय नसीम मिर्ज़ा चंगेज़ी भी मौजूद थे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराया।

सरकारी स्कूल-शिक्षकों के नाम शिक्षा मंत्री का पत्र

प्रिय शिक्षक साथियों!

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास के बेहतरीन नतीजों के लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई। साथ ही सरकारी स्कूलों में पहली बार आयोजित समर कैंप्स के सफल आयोजन के लिए भी आपको बधाई। पिछले एक साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई से लेकर पढ़ाई तक का एक अच्छा माहौल बना है। बहुत कुछ अच्छा हुआ है लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी ही कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने में सबसे बड़ी बाधा हैं।

- पिछले दिनों मैं 9वीं और 12वीं क्लास के लिए चल रहीं कुछ रेमेडियल क्लासेस में गया। एक स्कूल में मुझे 9वीं क्लास के बच्चों ने बताया कि उनके तीन अध्यापक अक्सर उनसे अभद्र गालियां देकर बात करते हैं, उनकी पिटाई तक करते हैं, उनसे बाहर से चाय मंगवाते हैं और ऐसा न करने वाले बच्चों को फेल तक कर देते हैं। ये शिकायतें किसी एक बच्चे ने नहीं की। पूरी क्लास के सारे बच्चे, नाम ले-लेकर, दुखी होकर ये शिकायतें कर रहे थे। इन्हीं बच्चों ने मुझे ऐसे अध्यापकों के बारे में भी बताया जो पढ़ाने में भी बहुत अच्छे हैं और व्यवहार में भी। शिकायतों की पुष्टि के लिए मैंने 12वीं क्लास में जाकर उन बच्चों से भी पूछा जो पिछले कई साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी बाकायदा नाम लेकर इन अध्यापकों की शिकायतें की। क्या आपको नहीं लगता कि छोटे-छोटे मासूम बच्चों के साथ गाली-गलौच और पिटाई करने वाले ऐसे अध्यापकों को एक दिन के लिए भी किसी स्कूल में रहने देना चाहिए? मैंने ऐसे अध्यापकों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई का फैसला लिया।
- इसी तरह एक और स्कूल में मैंने तीन ऐसे अध्यापकों को 'शो कॉज नोटिस' दिया है जो लगातार कई महीने से स्कूल में देरी से आ रहे थे। जब स्कूल के सारे अध्यापक समय से आ रहे हैं तो ये तीनों भी समय से क्यों नहीं आ सकते? इनकी वजह से स्कूल का माहौल खराब हो रहा था।

लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब मेरे एक्शन की प्रतिक्रिया में, शिक्षकों का एक समूह, इन फैसलों के विरोध में हंगामा करने पहुंचा। बाद में इसी समूह ने टीजीटी अध्यापकों की एक वर्कशॉप में जाकर भी हंगामा किया और वहां शामिल अध्यापकों को वर्कशॉप का बायकॉट करने के लिए उकसाया। वर्कशॉप में शामिल स्टॉफ के साथ बदतमीजी और मारपीट की। इनकी मांग है कि गाली-गलौच के आरोपी अध्यापकों के खिलाफ लिए गए एक्शन को वापस लिया जाए। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग बच्चों के साथ गाली-गलौच करने वाले शिक्षकों को सही मान रहे हैं। जब सरकारी स्कूलों से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहां माहौल बदल रहा है, तो ऐसे में गाली-गलौच करने वाले अध्यापकों के समर्थन में यह हरकतें कहां तक उचित है?

मैंने सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों की प्रतिभा की खुलेआम सराहना की है। मैंने पाया है कि हमारे 50 हजार अध्यापकों में से अधिकतर अपना काम विषम परिस्थितियों में भी बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक बहुत छोटा सा समूह ऐसा है जो स्कूल में समय पर न आने, क्लासरूम में न पढ़ाने, बच्चों के साथ अभद्रता से पेश आने, यहां तक कि पढ़ाई में रुचि रखने वाले साथियों का मजाक उड़ाने में शान समझता है। ऐसे छोटे से समूह की वजह से पूरा का पूरा सरकारी शिक्षक समाज लोगों का भरोसा खोता जा रहा है। इन्हीं वजह से सरकारी स्कूल का नाम आते ही ज्यादातर लोग यही कहते मिलेंगे- ''सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं होती।

सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे बिना हम अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देने की कल्पना नहीं कर सकते। नये क्लासरूम्स और नये स्कूल्स बनवाये जा रहे हैं। देश-विदेश की बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है, अध्यापकों को पढ़ाने की बेहतरीन सुविधाएं और स्वतंत्रता का माहौल बनाया जा रहा है। आप सबकी मेहनत से रिजल्ट अच्छा आया है। मेरा सभी अध्यापक साथियों से अनुरोध है कि देश और अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए समर्पण से काम करें। बच्चों की पढ़ाई में रुचि रखने वाले अपने एक-एक शिक्षक साथी के लिए ये सरकार कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन शिक्षा के काम में बाधा डालने वाले ऐसे चंद लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी।

जय हिंद

आपका
मनीष सिसोदिया
शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

श्री सज्जन सिंह यादव, निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 द्वारा प्रकाशित एवं आकांक्षा इम्प्रेशन्स, 18/36 स्ट्रीट नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–05 द्वारा मुद्रित